● वर्ष-4
● अंक-184
रायपुर, गुरुवार
13 मार्च 2025
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» यू बढ़ रही स्किल ब्रांड....

आत्मसमर्पण/ पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 को मंजूरी

साय कैबिनेट बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय

रायपुर। मुख्यमंत्री निवास में हुई कैबिनेट की बैठक खतम हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए ..मंत्रिपरिषद ने राज्य में नक्सल समस्या के समाधान के लिए ठोस पहल करते हुए छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति-2023 के स्थान पर छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/ पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को आर्थिक सहायता, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक-2025 विधानसभा के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

मुख्यमंत्री ने 27 फरवरी को फिल्म ''छावा'' को राज्य में टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी। मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में फिल्म छावा के प्रदर्शन पर प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किए जाने का अनुमोदन किया गया।

मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और वैज्ञानिक योजना तैयार करने के लिए राज्य जल सूचना केन्द्र का गठन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से समझौता ज्ञापन (एमओयू) करने की सहमति प्रदान की गई।

स्टेट वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर वर्षा, नदी और जलाशयों के स्तर, भूजल गुणवत्ता, गाद, नहरों में जल प्रवाह, फसल कवरेज, जलभृत मानचित्रण, भूमि और मिट्टी के डेटा सहित जल संसाधन संबंधी विभिन्न सूचनाओं का संग्रह, विश्लेषण और भंडारण करेगा।

एसडब्ल्यूआईसी, एनडब्ल्यूआईसीद्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफार्म की सहायता से जल संसाधन प्रबंधन के लिए प्रमाणिक डेटा उपलब्ध कराएगा। इससे नीति निर्माण, रणनीतिक निर्णय, मॉडलिंग, विश्लेषणात्मक उपकरणों के विकास और जल प्रबंधन को मजबूती मिलेगी।

मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के जल संसाधन विभाग के 09 बॉधों के सुधार कार्यों के लिए 522.22 करोड़ रूपए भारत सरकार के माध्यम से ऋण स्वीकृति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। इनमें मनियारी टैंक, घोंघा टैंक, दुधावा, किंकारी, सोंढूर, मूरूमसिल्ली (भाग-2), रविशंकर सागर परियोजना (भाग-2), न्यूज रूद्री बैराज और पेण्ड्रावन टैंक शामिल हैं।

मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में सुशासन और नीति क्रियान्वयन को मजबूत करने में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

यह योजना आईआईएम रायपुर और ट्रांसफार्मिंग रूरल इंडिया फाउण्डेशन नई दिल्ली के सहयोग से सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा संचालित की जाएगी। यह योजना छत्तीसगढ़ के मूल निवासी युवाओं के लिए होगी। इस कार्यक्रम को सुफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले फेलो को आईआईएम रायपुर द्वारा एमबीए के डिग्री प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक तौर पर चयनित फेलो को दो वर्ष की कुछ अवधि में आईआईएम रायपुर में शैक्षणिक सत्र में शामिल होना होगा तथा शेष अवधि में जिला/विभाग में राज्य की योजनाओं एवं कार्यक्रम हेतु कार्य करके जिला/विभाग को सहयोग प्रदान करना होगा। इस कार्यक्रम में होने वाले खर्च का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा साथ ही फेलो को प्रति माह स्टाईपेंड भी प्रदान किया जाएगा।

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ में भारत माला परियोजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार की प्राप्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच ईओडब्ल्यू के माध्यम से जांच कराने का निर्णय लिया है।

शाह लोस में पेश करेंगे सहकारी विवि पर विधेयक

नईदिल्ली। संसद के दोनों सदनों में बुधवार को कामकाज की सूची जारी की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पेश करेंगे, जबकि राज्यसभा में रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होगी।

अमित शाह ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद को एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने के लिए विधेयक पेश करेंगे, जिसे %त्रिभुवन% सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाएगा। इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाएगा।

विश्वविद्यालय सहकारी क्षेत्र में तकनीकी, प्रबंधन शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करेगा, सहकारी अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा तथा वैश्विक उत्कृष्टता के मानकों को प्राप्त करेगा। इसका उद्देश्य %सहकार से समृद्धि% के विजन को साकार करना और देश में संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से सहकारी आंदोलन को मजबूत करना है।केंद्रीय मंत्री सरबानंद सोनोवाल यह प्रस्ताव रखेंगे कि समुद्र के रास्ते माल ढुलाई से संबंधित वाहकों की जिम्मेदारियों, दायित्वों, अधिकारों और छूटों के बारे में विधेयक पर विचार किया जाए और इससे जुड़े या संबंधित मामलों पर चर्चा की जाए।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यह प्रस्ताव रखेंगे कि तेल क्षेत्र (नियमन और विकास) अधिनियम, 1948 में संशोधन करने वाला विधेयक, जिसे राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है, पर विचार किया जाए।

राज्यसभा में रेलवे मंत्रालय के कार्यों पर चर्चा का कार्यक्रम बताया गया है।बुधवार को संसद ने रेलवे (संशोधन) बिल 2024 को पारित किया, जिसे राज्यसभा ने मंजूरी दी। यह विधेयक रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन करने का प्रयास करता है, जिसका उद्देश्य रेलवे बोर्ड की शक्तियों को बढ़ाना और इस संस्था की कार्यकुशलता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। लोकसभा ने पिछले साल ही इस रेलवे (संशोधन) विधेयक 2024 को अपनी मंजूरी दे दी थी। विभिन्न स्थायी समितियां भी दोनों सदनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी।

मदर ऑफ डेमोक्रेसी की ओर से मॉरीशस को गिफ्ट

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपनी दो दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान मॉरीशस में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कहा कि भारत मॉरीशस में एक नई संसद बनाने में सहयोग करेगा। आज, प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम और मैंने भारत-मॉरीशस साझेदारी को बढ़ी हुई रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देने का फैसला किया। हमने तय किया कि भारत मॉरीशस में नई संसद भवन के निर्माण में सहयोग करेगा। यह लोकतंत्र की जननी मॉरीशस की ओर से मॉरीशस को एक उपहार होगा।उन्होंने कहा कि भारत और मॉरीशस न केवल हिंद महासागर से जुड़े हैं, बल्कि परंपराओं और संस्कृति से भी जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम आर्थिक और सामाजिक विकास की यात्रा में भागीदार हैं। हम हमेशा एक-दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। चाहे स्वास्थ्य हो, अंतरिक्ष हो या रक्षा, हम एक-दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं।

प्रमुख समाचार

मुंबई की अदालत ने आजमी को अग्रिम जमानत दी

मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रशंसा करने संबंधी टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में अग्रिम जमानत दे दी। महाराष्ट्र विधानसभा से 26 मार्च तक निलंबित आजमी को राहत देते हुए अदालत ने कुछ शर्तें लगाईं और उन्हें 20,000 रुपये का जमानत मुचलका भरने का निर्देश दिया। पिछले सप्ताह दक्षिण मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस थाने में महानगर के मानखुर्द-शिवाजी नगर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक आजमी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मुगल बादशाह की प्रशंसा करने वाली उनकी टिप्पणी को लेकर मामला दर्ज किया गया था। समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष आजमी ने कहा था कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान भारत की सीमाएं अफगानिस्तान और बर्मा (म्यांमा) तक थीं। औरंगजेब के शासनकाल का जिक्र करते हुए आजमी ने दावा किया था, ''हमारा जीडीपी का 24 प्रतिशत था और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था।'' औरंगजेब और मराठा राजा छत्रपति संभाजी महाराज के बीच लड़ाई के बारे में पूछे जाने पर आजमी ने इसे ''राजनीतिक लड़ाई'' करार दिया था।

ममता को बताया हिंदू विरोधी, टीएमसी ने किया पलटवार

नईदिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के बयान पर भाजपा सांसद और पश्चिम बंगाल भाजपा के उपाध्यक्ष जगन्नाथ सरकार ने कहा कि वह बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार हिंदू विरोधी सरकार है। पश्चिम बंगाल के हिंदू पीड़ित हैं और ममता बनर्जी इस मामले पर चुप हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने पलटवार करते हुए कहा कि हम इस तरह के बयान और मानसिकता का कड़ा विरोध और निंदा करते हैं। नेता प्रतिपक्ष को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने सवाल उठाए कि क्या भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इस तरह के बयान का समर्थन करेगा?

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी द्वारा भगवा पार्टी के नेताओं पर राज्य में नकली हिंदू धर्म लाने का आरोप लगाने के बाद बुधवार को भाजपा विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। टीएमसी सुप्रीमो की टिप्पणी बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की टिप्पणियों के जवाब में थी।

अलगाववादी संगठनों पर लगाया 5 साल का प्रतिबंध

नईदिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के दो संगठनों - अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत पांच साल की अवधि के लिए प्रतिबंधित समूह घोषित कर दिया। उमर फारूक की अध्यक्षता वाली एएसी और मसरूर अब्बास अंसारी की अगुवाई वाली छ्ययद्धरू पर गैरकानूनी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक मानी जाने वाली गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने अपनी अधिसूचना में कहा कि दोनों संगठनों के सदस्य आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने और जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी बयानों का प्रचार करने में शामिल रहे हैं। जेकेआईएम के लिए जारी एक अलग अधिसूचना में इसी तरह के आरोपों का हवाला देते हुए कहा गया कि यह समूह राष्ट्रीय एकता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों में शामिल है और इसके आतंकवादी समर्थन और भारत विरोधी प्रचार से संबंध हैं। इन कारणों का हवाला देते हुए, गृह मंत्रालय ने औपचारिक रूप से दोनों संगठनों को यूएपीए के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया।

सांप्रदायिक विवाद पैदा करने वाले बयान देने से बचें: पवार

मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने अपने कैबिनेट सहयोगी नितेश राणे द्वारा मुसलमानों के संबंध में दिए गए बयान को ''भ्रामक'' करार दिया और राज्य के नेताओं को संयम बरतने की सलाह दी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता नितेश राणे ने हाल में बयान दिया था कि मुसलमान छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना का हिस्सा नहीं थे। जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख पवार से राणे की इस टिप्पणी के संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि नेताओं को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से दिए गए बयानों से सांप्रदायिक तनाव पैदा न हो।

पवार ने कराड में कांग्रेस के दिवंगत नेता और राज्य के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण की जयंती पर उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बादकहा कि राजनीति में पक्ष या विपक्ष के ''कुछ नेता कभी-कभी ऐसे बयान दे देते हैं जो महाराष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए हानिकारक होते हैं। अतीत में, राज्य के नेताओं ने हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का प्रयास किया है और यह सुनिश्चित किया है कि विभिन्न समुदाय साथ मिलकर शांतिपूर्वक रह सकें।''

यूपी में होली से पहले मस्जिदों को तिरपाल से ढंका

शाहजहांपुर । इस बार होली 64 साल बाद रमजान के जुमे के दिन है। इससे पहले 1961 में 4 मार्च को होली और रमजान का शुक्रवार (जुमा) साथ-साथ था। रंग में भंग न पड़ जाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन अलर्ट है। प्रदेश के 10 जिलों में जुमे की नमाज का वक्त बदल दिया गया है। मस्जिदों को रंग-गुलाल से बचाने के लिए तिरपाल से ढंक दिया गया है। शाहजहांपुर में सबसे ज्यादा 67 मस्जिदों को तिरपाल और पन्नी से ढंका गया है। यहां लाट साहब के जुलूस के लिए पुलिस संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर रही है। एक हजार से ज्यादा पुलिस जवान दूसरे जिलों से आए हैं। शाहजहांपुर में जूता मार होली खेलने की परंपरा 300 सालों से चली आ रही है। होली के दिन यानी 14 मार्च को लाट साहब का लंबा-चौड़ा जुलूस निकलेगा। इसमें एक व्यक्ति को लाट साहब बनाकर भैंसा गाड़ी पर बिठाया जाता है। लोग उस पर रंग, जूते-चप्पल बरसाते हैं। शाहजहांपुर में लाट साहब के दो जुलूस निकाले जाते हैं, जिन्हें छोटे और बड़े लॉट साहब कहा जाता है। कोतवाल लाट साहब को सलामी देकर नेग देते हैं, इसके बाद जुलूस रोशनगंज, बेरी चौकी, अंटा चौराहा होते हुए थाना सदर बाजार क्षेत्र में प्रवेश करता है।

बाबा विश्वनाथ मंदिर पर जुलूस खत्म हो जाता

परिसीमन पर विवाद और डिजिटल मीडिया पर लगाम की मांग

आम जनता से कैसे जुड़ा है दोनों मुद्दा

संसद के बजट सत्र में लगातार कई मुद्दे उठ रहे हैं और सरकार की तरफ से इसको लेकर समाधान की भी कोशिश की जा रही है। हालांकि, परिसीमन को लेकर पहले ही दिन से जबरदस्त तरीके से हंगामा है। संसद के साथ-साथ विपक्ष बाहर भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में है। दूसरी ओर डिजिटल मीडिया को लेकर भी आज सदन में एक मांग उठी कि इसे कंट्रोल किया जाए। आज हम इन्हीं दोनों के विषय में बात करते हैं।

परिसीमन मुद्दे को लेकर संसद से सड़क तक जबरदस्त तरीके से हंगामा हो रहा है। खास करके दक्षिण भारत के राज्य केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि, केंद्र सरकार किसी भी भेदभाव से इनकार कर रही है। केंद्र यह भी कह रही है कि जो प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, उसको लेकर गलत बातें प्रसारित की जा रही है। संसद में भी परिसीमन मुद्दे को लेकर हंगामा लगातार देखने को मिला है। आज भी संसद में परिसीमन का मुद्दा उठा। डीएमके का साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ जनसंख्या के आधार पर परिसीमन नहीं होना चाहिए। इसमें सभी राज्यों को समुचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

आम जनता को लाभ

दरअसल, बढ़ती जनसंख्या के आधार पर समय-समय पर निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित की जाती है और इसी को परिसीमन कहा जाता है। यह प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि लोकतंत्र में आबादी के हिसाब से सभी का प्रतिनिधित्व हो सके और समान अवसर मिल सके। यही कारण है कि लोकसभा हो या विधानसभा, सीटों को समय-समय पर परिभाषित करने या पुनर्धारित करने के लिए परिसीमन किया जाता है। जनसंख्या में लगातार होते बदलाव की वजह से इसे करना जरूरी हो जाता है। इसका मतलब साफ है कि आम जनता के हित के लिए परिसीमन आवश्यक है तभी जनसंख्या और आबादी के हिसाब से सरकार द्वारा लोगों के लिए योजनाएं बनाई जा सकती है। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है और सभी को समान अवसर मिलता है।

विरोध क्यों

2011 के बाद से देश में जनगणना नहीं हुई है। इसे 2021 में किया जाना था। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से यह नहीं हो सका और अभी भी लंबित है। माना जा रहा है कि आने वाले एक या दो वर्षों में इसे किया जाएगा और उसके बाद परिसीमन होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि उत्तर भारत में जहां लोकसभा की सीटों में वृद्धि होगी। वहीं, दक्षिण भारत को इसका नुकसान या वर्तमान की स्थिति में ही रहना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तर भारत की आबादी ज्यादा बढ़ी है जबकि दक्षिण भारत में जनसंख्या नियंत्रित हुआ है। दक्षिण भारत के राज्यों को चिंता है कि परिसीमन के बाद संसद में उनका प्रतिनिधित्व कम हो सकता है जिसका मतलब साफ है कि उनकी राजनीतिक प्रभाव में गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है कि तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों की चिंताओं का समाधान किया जाएगा और कोई भेदभाव परिसीमन में नहीं होगा। हालांकि देखना दिलचस्प होगा की जनसंख्या और परिसीमन होता कब है क्योंकि अब तक इसकी चर्चा की शुरुआत नहीं हुई है।

डिजिटल मीडिया पर लगाम

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद दिलीप सैकिया ने लोकसभा में केंद्र सरकार से आग्रह किया कि डिजिटल मीडिया के नियमन के लिए कानूनी प्रावधान किया जाए। उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान यह मांग की। सैकिया ने कहा, ''मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन पोर्टल की बाढ़ आ गई है। बहुत सारे पोर्टल असत्य खबरें प्रसारित कर रहे हैं। इससे मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो रहा है।''

जनता के हित में कैसे

आज देश में लगभग 90 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास मोबाइल है। हम मोबाइल में लगातार जो देखते हैं, जिसमें खबरें भी होती हैं। यह रिल या फिर वीडियो फॉर्मेट में हम देखते हैं। डिजिटल मीडिया के होने की वजह से हमें अखबारों या फिर टीवी की जरूरत नहीं पड़ती। हम किसी भी प्रकार की जानकारी को तुरंत हासिल कर सकते हैं। डिजिटल मीडिया ने आज संसार के माध्यम को बहुत सरल और तेज बना दिया है। हालांकि, यह बात भी सत्य है कि डिजिटल मीडिया की वजह से असत्य चीजों का प्रसार भी बढ़ा है। कमाई के लिए भ्रामक खबरें भी डाली जाती है जिससे आम आदमी की जानकारी को तो नुकसान पहुंचता ही है, समाज में भी कई बार टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा आज के समय में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि हमारे मोबाइल के जरिए जो जानकारी हमें मिल रही है वह सत्य होनी चाहिए और प्रामाणिक होनी चाहिए और इसके लिए डिजिटल मीडिया के नियमन के लिए कानूनी प्रावधान जरूरी है। हालांकि, कई बार विवाद के बाद इसको लेकर मांग जरूर उठती है। हाल में ही हमने देखा कि किस तरीके से चुनाव को प्रभावित करने के लिए सरकार के मंत्रियों के बयान को ही तोड़-मोड कर पड़े पेश किया गया।

हाईकोर्ट में 17 मार्च से लागू होंगे नये रोस्टर

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायिक कार्यों के सुचारु संचालन के लिए 17 मार्च से नए रोस्टर लागू किए जाएंगे। इस बदलाव के तहत 4 डिवीजन बेंच और 13 सिंगल बैंच में न्यायाधीशों के कार्यों का विभाजन किया गया है। हाईकोर्ट प्रशासन ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।

हाईकोर्ट में इस बार चार डिवीजन बेंच का गठन किया गया है. जिनमें विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई होगी। डिवीजन बेंच एक में मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा एवं जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल होंगे। इस पीठ में लोकहित याचिकाओं (पीआईएल), रिट अपीली, बंदी प्रायक्षीकरण याचिकाओं। हैवियस कार्यस), आपराधिक संदर्भ मामलों, कर संबंधी मामलों एवं अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों की सुनवाई होगी।

डिवीजन बेंच दो में जस्टिस संजय के. अग्रवाल एवं जस्टिस संजय कुमार जायसवाल होंगे। इस पीठ की 2021 से संबंधित आपराधिक अपीलों, आपराधिक अवमानना याचिकाओं, धारा 482 दड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएनएस) के एफआईआर निरस्तीकरण से संबंधित मामलों की सुनवाई का अधिकार दिया गया है।

डिवीजन बेंच तीन में जस्टिस संजय अग्रवाल एवं जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल होंगे। इस पीठ में कर मामलों से संबधित रिट अपीले, व्यावसायिक अपीलीय खंडपीठ (कमर्शियल अपील बेंच के अंतर्गत आने वाले वाणिज्यिक विवादी एवं दीवानी मामलों की सुनवाई होगी।

डिवीजन बेच चार में जस्टिस रजनी दुबे एवं जस्टिस सचिन सिंह राजपूत होंगे। उस पीठ में 2019 से 2020 तक की आपराधिक अपीले, विशेष रूप से सौंपे गए मामले एवं संवैधानिक न्यायाधिकरणों (ट्रिब्यूनल्स) के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई होगी।

हाईकोर्ट में कुल 13 सिंगल बेच पुनर्गठित की गई है, जिनमें विभिन्न प्रकार के दीवानी, फौजदारी, सेवा एवं कर मामलों की सुनवाई होगी।

◆सिंगल बेच एक में जस्टिस संजय के अडवात मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम के तहत मामलों, थारा 482 सीआरपीसी एवं बीएनएनएस से संबंधित मामलों की सुनवाई करेंगे।

◆सिंगल बेच दो में जस्टिस संजय अग्रवाल 2013 से 2017 तक की आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाएं एवं 2022 से 2024 तक के आपराधिक अपीलों की सुनवाई करेंगे।

◆सिंगल बेच तीन में जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू 2017 से 2021 तक की सेवा से जुड़ी याचिकाएं एवं वाहन दुर्घटना दावों से संबधित अपीलों की सुनवाई करेंगे।

◆सिंगल बेंच चार में जस्टिस रजनी दुबे 2017 में 2019 तक की सेवा याचिका एवं दीवानी अपीलों की सुनवाई करेंगी।

◆सिंगल वेच पांच में जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास 2020 तक के दीवानी पुनरीक्षण (सिविल रिवीजन) एवं 2022 से 2024 तक की आपराधिक अपीलों की सुनवाई करेंगे।

◆छठे सिंगल बेंच में जस्टिस नरेश कुमार चंदवशी 2013 से 2022 तक की दीवानी अपीले एवं अन्य असाइन किए गए मामलों की सुनवाई करेंगे।

◆सातवें सिंगल बेंच में जस्टिस दीपक कुमार तिवारी 2015 से 2018 तक की दीवानी अपीलें एवं सेवा मामलों की सुनवाई करेंगे।

◆आठवें सिंगल बेंच में जस्टिस सचिन सिंह राजपूत 2022 से संबंचित नई सेवा याचिकाएं एवं विशेष मामलों की सुनवाई करेंगे।

◆नीचे सिंगल पेंच में जस्टिस राकेश मोहन पाडेय 2019 से 2021 तक की दीवानी अपील एवं विशेष रूप से सौंपे गए सामले सुनेंगे।

◆दसवें सिंगल बेंच में जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल सभी प्रकार की जमानत याचिकाजों एवं विशेष मामलों की सुनवाई करेंगे।

◆11वें सिंगल बेच में जस्टिस संजय कुमार जायसवाल अनुसूचित जाति-जनजाति आपाचार निवारण अधिनियम से जुड़े अपीलों की सुनवाई करेंगे।

◆12वें सिंगल बैंच में जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा दीवानी अपीले एवं 2017 के बाद के आपराधिक पुनरीक्षण मामले सुनेंगे।

◆13वें सिंगल बेंच में जॉस्टेस विभु दत्ता गुरु 2021 से संबंधित सभी प्रकार की आपराधिक अपीलें एवं सेवा मामलों की सुनवाई करेंगे।

इसके अलावा जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में विशेष पीठ (स्पेशल बंच) का गठन किया गया है, जी विशेष मामलों की सुनवाई करेगी। सभी प्रकार के अवमानना याचिकाओं एवं एफआईजार निरस्तीकरण से जुड़े मामलों को अलग-अलग बेंचों में विभाजित किया गया है। नया रोस्टर 17 मार्च 2025 से प्रभावी रहेगा और अगले आदेश तक लागू रहेगा।

प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज बना सिम्स जहां अब होगी एमबीबीएस की पढ़ाई हिन्दी में

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज बन गया है, जहां एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए हिंदी में पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। सिम्स की सेंट्रल लाइब्रेरी में 10 लाख रुपए की लागत से हिंदी माध्यम की पाठ्यपुस्तकें मंगाई गई हैं, जिससे खासकर हिंदी माध्यम से पढ़कर आए विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुरूप उन छात्रों की सुविधा के लिए लिया गया है, जो हिंदी माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर मेडिकल क्षेत्र में प्रवेश लेते हैं। हिंदी में पढ़ाई होने से छात्रों की कठिनाइयां कम होंगी और वे मेडिकल की जटिल अवधारणाओं को आसानी से समझ सकेंगे। हालांकि, महत्वपूर्ण तकनीकी शब्दावली अंग्रेजी में ही रखी जाएगी। अब मेडिकल के छात्र परीक्षा भी हिंदी में दे सकेंगे, हालांकि उनके पास अंग्रेजी में परीक्षा देने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। इस बदलाव से छात्रों को भाषा संबंधी कठिनाइयों से राहत मिलेगी और वे अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

कहा जा रहा है कि हिंदी में पढ़ाई होने से डॉक्टरों और मरीजों के बीच संवाद भी सरल होगा। वर्तमान में अधिकतर डॉक्टर अंग्रेजी में पर्चियां लिखते हैं, जिससे मरीज और उनके परिजनों को समझने में कठिनाई होती है। अब भविष्य में डॉक्टर दवाई की पर्चियां भी हिंदी में लिख सकेंगे, जिससे मरीजों को उपचार प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी।

सिम्स की सेंट्रल लाइब्रेरी में हिंदी माध्यम की पुस्तकों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराई गई है। इनमें नेत्र विज्ञान, रचना विज्ञान समेत विभिन्न चिकित्सा विषयों की हिंदी भाषा में पुस्तकें शामिल हैं। इससे हिंदी माध्यम के छात्रों को अपनी पढ़ाई में आसानी होगी। इसके बाद मध्य प्रदेश और बिहार के बाद, छत्तीसगढ़ तीसरा राज्य बन गया है जहां एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी।

आस्था का वो मेला जो पूरे देश में है विख्यात

■ **कदंब के पेड़ पर बांधा जाता है मन्नत का नारियल**

बालोद। छत्तीसगढ के बालोद व दुर्ग जिले की सीमा पर बसा एक गांव है ओटेबंद बगीचा, जो बालोद जिले में गुंडरदेही ब्लॉक में आता है। ओटेबंद के विष्णुधाम मंदिर में मेला लगाता है। इस गांव के मंदिर की अपनी विशेष पहचान है। यहां एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान विष्णु क्षीरसागर की मुद्रा में विराजमान हैं। यहां फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष को मेला आयोजित होता है। 11 दिन से यहां मेला लगा हुआ है और इसकी शुरुआत वर्ष 1961 से हुई थी। यहां पूरे देश भर से साधु-संत आते हैं और यहां एक ऐसा कदंब का वृक्ष है, यहां श्रद्धालुओं की मन्नत पूरी होती है। आइए जानते है इस मंदिर की विशेषता और इस मेले का महत्व।

बालोद और दुर्ग जिले में यह एकलौता मंदिर है। जहां पर भगवान विष्णु शयन और लक्ष्मी के पैर दबाते क्षीरसागर में आराम की मुद्रा को दिखाया गया है। इस गांव के मंदिर में आप वृहद रूप से एक बड़े क्षेत्र पर बने इस मूर्तियों की श्रृंखला को देखकर आश्चर्य रह जाएंगे कि इसकी बनावट बहुत ही सुंदर है। हर कोई जब इस मंदिर में जाता है तो इस क्षीरसागर रुपी मुद्रा को देखने के लिए आतुर होता है। और यहां पहुंच कर लोग भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित अन्य देवी-देवताओं के दर्शन करते है।

मंदिर समिति के सदस्य एवं स्थानीय जनपद अध्यक्ष पुरुषोत्तम लाल चंद्राकर ने बताया कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यह मेला लगता है और यह मेले के पूर्णाहुति का समय है। 1961 से यहां 11 दिनों तक महायज्ञ का आयोजन होता है। मंदिर की स्थापना 1993 से शुरू हुई थी, 1996 में पूरी हुई और सनातन हिन्दू महर्षि करपात्री महराज यहां आए। उन्होंने इस तीर्थ को तपोभूमि की संज्ञा दी और यहां चार शंकराचार्य का आगमन भी हो चुका है।

मंदिर समिति के संस्थापक सदस्य वीरेंद्र कुमार दिल्लीबार ने बताया कि यहां सबसे बड़ी मान्यता है कि कदंब के वृक्ष पर सच्ची आस्था से मांगी गई श्रद्धालु की हर मन्नत पूरी होती है। उन्होंने कहा कि इंदौर का एक परिवार जिनके कोई संतान नहीं थे उन्होंने यहां पर मन्नत मांगी और एक वर्ष के भीतर उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हुई। एक व्यक्ति जिसका ट्रक घर से गायब हो गया था, उसने इस जगह पर मन्नत मांगी और उसका ट्रक दो दिनों के भीतर मिल गया। उन्होंने कहा जिन्हें मन्नत मांगना होता है, वह इस कदंब की वृक्ष में जहां पर राधा रानी विराजमान हैं, श्री कृष्णा विराजमान हैं, वहां नारियल बांधते हैं।

यहां पर भगवान विष्णु महायज्ञ का आयोजन होता है, जो कि अनवरत 11 दिनों तक चलता है और अभी हम मेला समापन की ओर हैं और इस मेले की सबसे खास बात यह है कि पूरे छत्तीसगढ़ सहित देश के कोने-कोने से लोग यहां पर आते हैं।

जनपद चुनाव में बवाल भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के बरमकेला में जनपद पंचायत चुनाव के दौरान जबरदस्त बवाल हो गया। भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पहले तीखी बहस हुई और फिर मामला हाथापाई तक पहुंच गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मौके पर मौजूद पुलिस विवाद को रोकने में नाकाम रही। वहीं स्थिति को नियंत्रण करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

जानकारी के मुताबिक, भाजपा प्रभारी कैलाश नायक की गाड़ी से जनपद सदस्यों को छीनने के प्रयास के दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ता भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर धक्का-मुक्की और मारपीट हुई। देखते ही देखते पंचायत कार्यालय के बाहर तनाव की स्थिति बन गई और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट गई। बढ़ते विवाद को देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। पुलिस लगातार दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश कर रही है।

वहीं कड़ी सुरक्षा और विवाद के बीच हुए चुनाव में तमाम कोशिशों के बावजूद भाजपा प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की डॉक्टर विद्या किशोर ने चुनाव जीतकर जनपद पंचायत अध्यक्ष का पद हासिल कर लिया है।

डोंगरगढ़-खैरागढ़ में बाघ, तेंदुआ और दुर्लभ प्रजातियों का है बसेरा

संरक्षण से बन सकता है जैव विविधता का केंद्र

खैरागढ़-डोंगरगढ़। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ और खैरागढ़ केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए भी जाने जाते हैं। यहां के जंगलों में अनगिनत दुर्लभ और संरक्षित वन्य प्रजातियों का बसेरा है। यहां पक्षियों की 290 प्रजातियां पायी जाती हैं।

हाल ही में हुए एक विस्तृत अध्ययन ने इस क्षेत्र की वन्यजीव समृद्ध संपदा को उजागर किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यदि सही दिशा में प्रयास किए जाएं, तो यह क्षेत्र जैव विविधता संरक्षण का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। हाल ही में एम्बियंट साइंस नामक वैज्ञानिक जर्नल में प्रकाशित एक शोध में यहाँ की अद्भुत जैव विविधता देखने को मिली है।

अध्ययन में कुल 35 स्तनधारी प्रजातियों की पहचान की गई, जिनमें कई दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियां शामिल हैं। बाघ, तेंदुआ और भारतीय पैंगोलिन जैसे वन्यजीवों की मौजूदगी खैरागढ़ और डोंगरगढ़ के जंगलों में दर्ज की गई है, जबकि खतरों में शामिल कुछ प्रजातियां जैसे भालू और चौसिंघा यहां नियमित रूप से पाए जाते हैं। अध्ययन के दौरान कई ऐसे रोमांचक क्षण आए जब शोधकर्ताओं ने दुर्लभ जीवों की गतिविधियों को

नजदीक से देखा।

इस शोध में प्रकृति शोध एवं संरक्षण वेलफेयर सोसायटी के प्रतीक ठाकुर और डॉ दानेश सिन्हा के साथ छत्तीसगढ़ के मशहूर ऑर्निथोलॉजिस्ट ए एम के भरोस और पक्षीप्रेमी और वर्तमान में सीईओ जिला पंचायत कोंडागांव में पदस्थ अविनाश भोई शामिल रहे।

शोधकर्ताओं ने बताया यहां के जंगलों में बाघों की उपस्थिति के प्रमाण 2020 से आज तक मिल रहे हैं। बाघ के यहां स्थाई निवास के दावे भी किए जा रहे हैं, इसपर गहन अध्ययन की जरूरत है। इस इलाके की वन्यजीव संपदा जितनी अद्भुत है, उतनी ही चुनौतियों से भी घिरी हुई है। जंगलों का कटाव, खेती का बढ़ता दायरा और अवैध शिकार जैसी समस्याएं इन जीवों के अस्तित्व के लिए खतरा बन रही हैं।

स्लॉथ बियर,पेंगोलिन (शाल खपरी),हिरण और तेंदुए जैसी प्रजातियों के साथ मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं। ग्रामीणों के बीच कई अंधविश्वास भी प्रचलित हैं, जिसके कारण कई बार वन्यजीवों का शिकार किया जाता है। उदाहरण के लिए, पैंगोलिन की स्केल और तेंदुए के दाँत और नाखूनों की तस्करी बढ़ती जा रही है, जिससे इनकी आबादी खतरे में पड़ गई है।

यहां के जंगल कान्हा नेशनल पार्क, भोरमदेव अभयारण्य और नवेगांव टाइगर रिजर्व से जुड़े हुए हैं। ऐसे में इस विशाल वन क्षेत्र और समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित कर इसे मध्यभारत में चल रहे वन्यजीव संरक्षण कार्य को बल मिल सकता है।

डोंगरगढ़ और खैरागढ़ दोनों पहले ही पर्यटन स्थल के रूप में विकसित और विख्यात हैं। अगर यहां के जंगलों को संरक्षित कर सामुदायिक संरक्षण रिजर्व घोषित किया जाए तो पर्यटन का और भी अधिक महत्त्व बढ़ जाएगा। इससे न केवल वन्यजीवों को सुरक्षित आवास मिलेगा, बल्कि स्थानीय समुदायों को भी संरक्षण में शामिल किया जा सकेगा। स्थानीय प्रशासन और ग्रामीण मिलकर काम करें, तो यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र बन सकता है।

छत्तीसगढ़
प्रमुख समाचार

कांगेर घाटी को यूनेस्को ने किया विश्व धरोहर के रूप में शामिल

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है, जो कि छत्तीसगढ़ का पहला स्थल है, जिसे इस सूची में चयनित किया गया है। इस उपलब्धि पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसे राज्य के लिए गर्व की बात बताई है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में प्राकृतिक विरासत श्रेणी में जगह मिली है, अब आने वाले वर्ष में इस स्थल को नॉमिनेशन लिस्ट में शामिल करने की कोशिश सरकार की ओर से की जाने की बात कही जा रही है, लिस्ट में शामिल होने के बाद कांगेर घाटी को विश्व धरोहर की स्थाई सूची में जगह मिल सकती है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इस उपलब्धि को साझा करते हुए इसे प्रदेश के लिए ऐतिहासिक पल बताया, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का क्षण है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थाई सूची में शामिल किया गया है। कांगेर घाटी की जैव विविधता और सुंदर जलप्रपात इसे अनमोल बनाते हैं।

सरकारी जमीन को अपने नाम कराकर बेचा, गिरफ्तार

बलरामपुर। रामानुजगंज थाना क्षेत्र में फर्जी दस्तावेज के जरिए सरकारी जमीन को एक शख्स ने अपने नाम कराया। फिर उसे एक कोल माइनिंग कंपनी को बेच दिया। दस साल पुराने इस मामले में फरार चल रहे आरोपी को रामानुजगंज पुलिस ने झारखंड के गढ़वा से गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बलरामपुर के रामानुजगंज थाना क्षेत्र के इंदरपुर खोरी गांव में 250 एकड़ सरकारी जमीन से जुड़ा यह मामला है। इस जमीन के पहले फर्जी दस्तावेज तैयार कराए गए और आरोपी ने जमीन अपने नाम कराया। फिर उसने कोल माइनिंग कंपनी को बेच दिया। रामानुजगंज थाना प्रभारी रमाकांत तिवारी ने बताया कि रामानुजगंज थाना क्षेत्र के इंदरपुर खोरी गांव में सरकारी भूमि पर छोटे बड़े झाड़ थे। आरोपियों ने संगठित गिरोह बनाकर फर्जी दस्तावेज तैयार कराया और लगभग 250 एकड़ भूमि को बेच दिया था। इस मामले में तत्कालीन नायब तहसीलदार की शिकायत पर पुलिस ने साल 2015 में एफआईआर दर्ज किया था।

गीला कचरा से कंप्रेस्ड बायोगैस 10 एकड़ में लगेगा यूनिट

कोरबा। शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के दौरान बड़े पैमाने पर कचरा निकलता है। इसमें सूखा और गीला कचरा को अलग किया जाता है। सूखा कचरे से निकलने वाले विभिन्न सामान जैसे प्लास्टिक, पॉलिथिन को सेग्रिगेट किया जाता है। जबकि गीला कचरे को दूसरे तरीके से नष्ट किया जाता है। अब इसी गीला कचरा से नगर निगम कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने की तैयारी कर रहा है। गीला कचरा से कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने के लिए नगर निगम क्षेत्र में एक यूनिट का निर्माण किया जाना है। लगभग 10 एकड़ जमीन पर यह महत्वाकांक्षी परियोजना आकर लेगी। कंप्रेस्ड बायोगैस, संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) एक अक्षय ईंधन है। ये बायो गैस कृषि अवशेषों, गोबर, और गीला कचरा से बनाया जाता है। इसका उपयोग गाड़ियों, उद्योगों में सीएनजी के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने ही कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देने की रणनीति बनाई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जैव ईंधन के क्षेत्र में 2030 तक देश भर में 20 फीसदी को ग्रोथ का टारगेट रखा था।

जशपुर में एनसीसी कैडेट्स के लिए फ्लाइंग ट्रेनिंग

जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर के आगडीह हवाई पट्टी पर अब एनसीसी कैडेट्स को हवा में उड़ान भरने का सुनहरा मौका मिल रहा है।3 सीजी एयर स्क्वॉड्रन रायपुर के बैनर तले इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरु किया गया है।जिसके तहत राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) निदेशालय मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ ने अपने सबसे बड़े समूह मुख्यालय, रायपुर के तत्वावधान में फ्लाइंग प्रशिक्षण की सुविधा जशपुर तक बढ़ाई है। इससे पहले ये ट्रेनिंग केवल रायपुर हवाई अड्डे तक सीमित था। इस प्रशिक्षण में एनसीसी सीनियर डिवीजन के कैडेट्स लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। जिन्हें टू सीटर माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट के माध्यम से उड़ान भरने का अनुभव दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान कैडेट्स को छोटे हवाई जहाज से उड़ान भरने, रनवे पर लैंड करने, विमान के कॉकपिट और उसके हिस्सों के संचालन की बुनियादी जानकारी प्रदान की जा रही है। यह पहल उन युवा एविएटर्स (विमान चालकों) के लिए एक बड़ा अवसर है जो भविष्य में इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं।

जशपुर जिला पंचायत में भाजपा का कब्जा

जशपुर। भारतीय जनता पार्टी ने जशपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में जीत हासिल की है। दोनों ही पद के भाजपा अधिकृत उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। भाजपा अधिकृत उम्मीदवार सालिक साय ने अध्यक्ष पद पर निर्विरोधित जीत दर्ज की। वहीं शौर्य प्रताप सिंह को भी उपाध्यक्ष पद के चुनाव में जीत मिली है। जीत के बाद उनके समर्थकों में भारी उत्साह है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में तीन जिला पंचायतों को छोड़कर बाकी सभी जगह जिपं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो चुका है। अभी रायपुर, जशपुर और सुकमा में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव बाकी है। यहां चुनाव की तारीखों में फिर से बदलाव किया गया है। पहले यह चुनाव 12 मार्च होना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इसे संशोधित कर दिया गया है। अब यह चुनाव 20 मार्च को होगा। जिला प्रशासन ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया है। 12 जिलों में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का सीट अनारक्षित था, जिसमें से 9 जिलों में ओबीसी अध्यक्ष और 8 जिलों में ओबीसी उपाध्यक्ष चुने गए हैं।

सहायक आयुक्त के घर फिर से पहुंची एसीबी-ईओडब्ल्यू की टीम

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक बार फिर एसीबी-ईओडब्ल्यू की कार्रवाई देखने को मिली है। भ्रष्टाचार के मामले में घिरे सहायक आयुक्त आनंद सिंह के घर पर आज सुबह से एसीबी की टीम जांच कर रही है।

बता दें कि बीते रविवार को भी एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने सहायक आयुक्त आनंद सिंह के घर दबिश दी थी, लेकिन उनकी अनुपस्थिति के कारण मकान को सील कर दिया गया था। जिसके बाद आज फिर से टीम ने उनके घर पहुंचकर तलाशी शुरू कर दी है।

रविवार को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ईओडब्ल्यू) की संयुक्त टीम ने बस्तर संभाग के बीजापुर और सुकमा में बड़े पैमाने पर छापेमारी की थी। इस दौरान सहायक आयुक्त के जगदलपुर के धरमपुरा स्थित मकान के साथ-साथ उनके दो रिश्तेदारों के बैलाबाजार और धरमपुरा स्थित अन्य मकानों पर भी दबिश दी गई थी। इसके अलावा एसीबी और ईओडब्ल्य की टीम ने सुकमा के डीएफओ (वन मंडल अधिकारी) समेत कई कारोबारियों के ठिकानों पर भी छापा मारा था। इस कार्रवाई के लिए रायपुर से विशेष टीम बस्तर संभाग पहुंची थी।

इलाज कराने महिला पहुंची थी डॉक्टर के पास, इंजेक्शन लगते ही बिगड़ी तबीयत

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही का खौफनाक नतीजा सामने आया है। बसंतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भलोईझोर में एक महिला को शरीर में दर्द की शिकायत थी, लेकिन इलाज कराने गई तो वापस घर नहीं लौट पाई। झोलाछाप डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया, जिसके तुरंत बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, मृतिका लक्ष्मीनिया (58 वर्ष) के शरीर में दर्द था, जिसके चलते परिवार ने गांव के झोलाछाप डॉक्टर विनोद वर्मा से इलाज कराया। डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन लगाया, जिसके तुरंत बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। हालत बिगड़ने पर उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतिका के परिजनों ने बताया कि मंगलवार की शाम करीब 4 बजे उन्होंने झोलाछाप डॉक्टर को बुलाया था। डॉक्टर ने बिना किसी जांच के महिला को इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। इसके बाद परिजन उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि झोलाछाप डॉक्टर बिना किसी डिग्री के इलाज करता था और गलत दवाइयां व इंजेक्शन लगाता था। उन्होंने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

सरेंडर करने वाले नक्सली के खिलाफ सड़क पर उतरे ग्रामीण, तहसीलदार को ज्ञापन

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में दिनेश मोडियाम नाम के एक नक्सली ने हाल ही में सरेंडर किया है। माओवादी दिनेश मोडियाम ने अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सरेंडर किया है। अब ग्रामीणों ने दिनेश मोडियाम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

गंगालूर में ग्रामीणों ने दिनेश मोडियाम के आत्मसमर्पण और उसको मिलने वाली सरकारी सुविधाओं को लेकर विरोध जताया। ग्रामीणों ने तहसीलदार को एक ज्ञापन भी दिया, जिसमें दिनेश मोडिया को पुनर्वास नीति के तहत मिलने वाले लाभ को लेकर नाराजगी जताई गई है।

ग्रामीणों का कहना है कि दिनेश मोडियाम पर 100 से ज्यादा जवानों की हत्या की घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। उसकी वजह से कई बेनुगाहों का घर उजड़ गया है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि दिनेश मोडियाम की वजह से 150 से ज्यादा गांव विकास से दूर हैं। ग्रामीणों ने यह चेतावनी भी दी है कि यदि सरकार दिनेश मोडियाम को पुनर्वास नीति के तहत लाभ देती है तो इसके विरोध में जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे। ग्रामीणों की मांग है कि दिनेश मोडियाम को फांसी की सजा दी जाए।

बता दें कि 3 मार्च को पश्चिम बस्तर डिविजन के गंगालूर एरिया कमेटी सचिव व छ्ङ्कष्टरू दिनेश मोडियम ने पत्नी और बच्चे के साथ बीजापुर पुलिस के सामने सरेंडर किया था। उस पर 8 लाख रुपये का इनाम घोषित था। सुरक्षा बलों के जवानों को उसकी कई दिनों से तलाश थी। दिनेश मोडियम गंगालूर इलाके का हार्ड कोर नक्सली है और 100 से भी ज्यादा हत्याओं में शामिल रहा है।

संक्षिप्त समाचार

छत्तीसगढ़ एसएसई प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम जारी

रायपुर। सीजीपीएससी ने राज्य सेवा परीक्षा 2024 के परिणाम जारी कर दिए हैं। इस परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट (psc.cg.gov.in) के माध्यम से परिणाम देख सकते हैं। भर्ती अभियान का लक्ष्य 246 रिक्तियों को भरना है। परिणाम और कट-ऑफ आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2024 का पूरा परिणाम, जिसमें अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक, नाम, जन्मतिथि और वर्गवार/उपवर्गवार कट-ऑफ अंक शामिल हैं। परीक्षा परिणाम के आधार पर, राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा 2024 के लिए कुल 3737 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। पहले यह संख्या 3690 निर्धारित थी, लेकिन वर्गवार/उपवर्गवार अर्ह अभ्यर्थियों की उपलब्धता के आधार पर यह बढ़कर 3737 हो गई। चयनित अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा 26, 27, 28 और 29 जून 2025 को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन प्रक्रिया और अन्य जरूरी जानकारी आयोग द्वारा जल्द ही जारी की जाएगी।

होली से पहले रायपुर पुलिस ने करोड़ों का कैश बरामद किया

रायपुर। राजधानी पुलिस होली पर्व को देखते हुए शहर के कई इलाकों में चेकिंग पॉइंट बनाकर गाड़ियों की तलाशी ले रही है। मंगलवार देर रात चेकिंग के दौरान आमानाका थाना अंतर्गत एक इनोवा गाड़ी से पुलिस ने लगभग 1 करोड़ 68 लाख रुपए बरामद किए हैं। आजाद चौक सीएसपी अमन झा ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी। जिसके आधार पर पुलिस ने इनोवा वाहन को रोक कर चेकिंग की। गाड़ी में लगभग ढाई करोड़ कैश रखा हुआ था। इनोवा गाड़ी पर नंबर 23 क्क॥ 8886 द्ध लिखा हुआ है। इस गाड़ी में एक अलग से डेक बनाकर कैश रकम को छुपा कर रखा गया था। इस मामले में पुलिस ने ड्राइवर सहित 2 आरोपियों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि पैसों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्हें सिर्फ महाराष्ट्र के नागपुर के पास गाड़ी बदलने को कहा गया था। लेकिन उससे पहले रायपुर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। करोड़ों रुपये मिलने के मामले में रायपुर पुलिस आरोपियों से विस्तार से पूछताछ की जा रही है। आखिर इतना पैसा कहां से आया और कहां जाने वाला था। यह स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस को आशंका है कि करोड़ों की रकम हवाला की हो सकती है।

होली के दिन बदला जुम्मे की नमाज का समय

रायपुर। होली के दिन शुक्रवार को छत्तीसगढ़ की मस्जिदों में नमाज के वक्त में बदलाव किया गया है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ। सलीम राज ने बताया, सामाजिक समरसता बनी रहे, इस वजह से यह फैसला लिया गया है। ज्यादातर मस्जिदों में दोपहर एक बजे होने वाली नमाज अब 2 से 3 बजे के बीच होगी। शुक्रवार को होली है, इस वजह से यह बदलाव किया गया है। सभी मस्जिदों के पदाधिकारी को इस संबंध में वक्फ बोर्ड की ओर से पत्र भेज दिया गया है। इस बार शुक्रवार को होली है। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं। दोपहर 12 बजे जोहर की नमाज होती है। इस नमाज को पढ़ने के लिए नमाजी मस्जिद के लिए निकलेंगे तो विवाद की आशंका है इसलिए छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ये निर्णय लिया है और सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय का बीजेपी ने स्वागत किया है।

छत्तीसगढ़ डाक सर्किल के नए सीपीएमजी होंगे सुवेंदु स्वैन

रायपुर। भारतीय डाक सेवा 1990 बैच के अधिकारी सुवेंदु स्वैन छत्तीसगढ़ डाक सर्किल के नए सीपीएमजी होंगे। यह पद बीते दो महीने से रिक्त था और मप्र के सीपीएमजी दोहरे प्रभार में थे। श्री स्वाइन ओडिशा से प्रमोशन पर छत्तीसगढ़ पदस्थ किए गए हैं।

दुर्ग-निजामुद्दीन-दुर्ग हमसफर एक्सप्रेस में एसी-3 कोच की सुविधा 18 व 19 को

रायपुर। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की बेहतर यात्रा सुविधा व अधिकाधिक यात्रियों को कंफ़र्म बर्थ उपलब्ध कराने हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली गाड़ी संख्या 22867/22868 दुर्ग-निजामुद्दीन-दुर्ग हमसफर एक्सप्रेस में एक एसी-3 कोच की सुविधा अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई जा रही है । यह सुविधा गाड़ी संख्या 22867 दुर्ग-निजामुद्दीन हमसफर एक्सप्रेस में 18 मार्च को तथा गाड़ी संख्या 22868 निजामुद्दीन-दुर्ग हमसफर एक्सप्रेस में 19 मार्च को उपलब्ध रहेगी । इस सुविधा की उपलब्धता से इस गाड़ी में यात्रा करने वाले अधिकाधिक यात्री लाभान्वित होंगे।

विधानसभा में उड़े रंग-गुलाल, रंग में रंगे नजर आए पक्ष-विपक्ष के सदस्य

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। यह एक ऐसा मौका था जब एक-दूसरे पर सियासी तीर चलाने की बजाए पक्ष-विपक्ष के तमाम सदस्य खुशी-खुशी एक साथ होली के रंग में रंगे नजर आ रहे थे। खुशी के इस मौके पर केवल विधायक ही नहीं विधानसभा को कवर करने वाले पत्रकारों के साथ विधानसभा के अधिकारी-कर्मचारी भी शरीक हुए।

भारतमाला परियोजना में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग

■ **सीएम साय ने कहा- आपने सीबीआई को बैन कर रखा था**

रायपुर। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भारतमाला परियोजना में गड़बड़ी को लेकर प्रश्न किया। उन्होंने पूछा- 13 मूल खाताधारकों के खसरे को 54 टुकड़ों में बांटा गया। एक गांव में एक मूल खसरे को 4 टुकड़े किए गए। तीसरे गांव में चार मूल खसरे को 33 टुकड़े किए गए। रायपुर के अभनपुर तहसील के चार गांवों के मुआवजा प्रकरण पर प्रश्न उठाया है। उसमें लगभग 43 करोड़ 19 लाख का आर्थिक नुकसान केंद्र सरकार को कराया गया। राजस्व मंत्री ने ये सब बातें स्वीकार की है। हमारी मांग है कि केंद्र का पैसा है राज्य का हिस्सा भी हो सकता है। पूरे भारतमाला की जो सड़क बन रही है उसमें 350 करोड़ से ज्यादा अतिरिक्त भुगतान किया गया है। राजस्व मंत्री ने स्वीकार किया है। दो अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। बहुत बड़ा प्रश्न है। आपसे निवेदन है कि सीबीआई से जांच करा दीजिए। मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है।

राजस्व मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि भारतमाला परियोजना में गड़बड़ी हुई है। दो तीन तरह की गड़बड़ी हुई है। अधिसूचना जारी होने के बाद रकबे का टुकड़ा किया गया। जमीन एक बार अधिग्रहित की गई थी

उसे दोबारा भूअर्जन किया गया। जिसे मुआवजा मिलना था उसे ना देकर दूसरे को मुआवजा दिया गया। ट्रस्ट को मुआवजा ना देकर निजी व्यक्ति को मुआवजा दिया गया। इस पर अभी भी शिकायतें आ रही है। कई लोगों पर कार्रवाई की गई है। इसी गड़बड़ी को रोकने हमारी सरकार ने नए नियम बनाए हैं। मामले में जांच की जा रही है, कार्रवाई भी जारी है।

नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने मंत्री के गड़बड़ी को मानने पर धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा 43 करोड़ 19 लाख का अतिरिक्त भुगतान प्रकाशन होने के बाद इसका बंटवारा हुआ। कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया, सीएम को दिखाना चाहता हूं, एक प्रश्न का उत्तर है। जब गड़बड़ी स्वीकार कर रहे हैं तो मेरी मांग है कि जिन जिन अधिकारियों ने गड़बड़ी की है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर जेल भेजा जाए। सीबीआई से जांच करना स्वीकार कर लें। जांच भी हो जाएगी और आने वाले लोग सतर्क भी हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है।

मंत्री ने कहा जैसे जैसे शिकायत मिल रही है, कार्रवाई की जा रही है। पिछले विधानसभा सत्र में विधेयक पारित किया गया है। लापरवाही और गलती करने वालों को निलंबित किया जा रहा है। महंत ने कहा निलंबन के बदले एफआईआर होनी चाहिए। ये मायाजाल ऐसा है कि कहीं ना कहीं जाल को काट कर निलंबित अधिकारी काम करने लगते हैं। कई मामलों में ऐसा हुआ हैं। वो हमारे शरीर को जमीन को तार तार कर चले आ रहे हैं। इसलिए बहुत शांति से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि भारतमाला में हुई गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने की मांग मान लें।

राजस्व मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि जितने तरह की शिकायतें मिल रही है, उस पर कार्रवाई हो रही है।

महंत ने कहा सीबीआई से जांच का निर्णय मुख्यमंत्री ही ले सकते हैं। सीएम इस पर बता दें तो बेहतर होगा। जब मैं खड़े होकर पिछले सरकार के घपले की बात कर रहा हूं तब भी आप तैयार नहीं हो रहे हैं।

राजस्व मंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की शिकायत गंभीर है। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो रही है, विश्वास दिला रहा हूं जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस पर विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने टोका और कहा कि नेता प्रतिपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उस पर जवाब दीजिए। मंत्री टंकराम ने कहा कि संभाग अध्यक्ष से जांच कराई जाएगी।

सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि राजस्व मंत्री ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। कुछ कमी होगी तो बताइए उस पर कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा कि पिछले कांग्रेस कार्यकाल में सीबीआई को बैन किया गया था।

महंत ने कहा कि हमने सीबीआई को बैन किया था लेकिन आपकी सरकार ने फिर से सीबीआई जांच हो रही है। इसलिए आपसे ये मांग है कि भारतमाला परियोजना में गड़बड़ी की सीबीआई जांच करा दें। विधायकों की समिति बनाकर जांच करा लें। मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि संभाग आयुक्त से जांच कराई जाएगी। इसके बाद विधायक उमेश पटेल भी बीच में कूद पड़े। जिसके बाद विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने संतुष्टजनक जवाब नहीं मिलने पर सदन से बहिर्गमन कर दिया।

केलो प्रोजेक्ट में भू-अर्जन में गड़बड़ी पर उबला सदन

विधानसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केलो प्रोजेक्ट में जमीनों की अफरा-तफरी का आरोप लगाया। विपक्षी सदस्यों ने सदन की समिति से मामले की जांच कराने की मांग को लेकर हंगामा मचाया। इस पर मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन किया। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने प्रश्नकाल के दौरान केलो प्रोजेक्ट में भू-अर्जन का मुद्दा उठाते हुए पूर्णता को लेकर सवाल पूछा। मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि परियोजना 80% पूरी हो चुकी है। प्रोजेक्ट में 23 प्रकरण लंबित होने के अलग-अलग कारण हैं। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रोजेक्ट में जमीनों की अफरा-तफरी का आरोप लगाते हुए सदन की समिति से मामले की जांच कराने की बात कही। मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि विभागीय रुप से जांच कराई जाएगी। इस पर भूपेश बघेल ने कहा कि सदन की समिति से जांच होनी चाहिए। इस पर विपक्ष ने हंगामा मचाते हुए नारेबाजी की। इसके साथ मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

राज्य सरकार की अनुमति के बिना जलाशय की जमीन जिंदल स्टील को आबंटित करने का मामला सदन में उठा

रायपुर। सरकार की अनुमति के बिना केलो परियोजना के लिए जलाशय की जमीन जिंदल स्टील को आबंटित करने का मामला बुधवार को विधानसभा में कांग्रेस के विधायक उमेश पटेल ने उठाया। इस पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने अनभिज्ञता जताई और सदन समिति से जांच कराने की विपक्ष की मांग को नामंजूर कर दिया। इससे नाराज होकर कांग्रेस के विधायकों ने सदन से बर्हिगमन कर दिया।

प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के उमेश पटेल ने मंत्री से यह पूछा कि क्या केलो परियोजना की कोई जमीन किसी इन्डस्ट्रीज को ट्रांसफर की गई है। मंत्री वर्मा ने कहा विधायक जो शिकायत कर रहे हैं उसकी जानकारी सरकार के पास नहीं है। उमेश पटेल ने मंत्री को जानकारी दी कि अगस्त 24 में ग्राम जोरापाली के खसरा नंबर 5/2 समेत 22 खसरों की जमीन जिंदल स्टील के नाम पर ट्रांसफर की गई है। मैंने और ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की थी लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस शिकायत पर अब

कार्रवाई करेंगे। राजस्व मंत्री ने कहा शिकायत दे दे तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।

इस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा बिना राजस्व मंत्री की कमेटी की अनुमति के बिना इतनी बड़ी जमीन का लैंड यूज बदल गया और मंत्री को पता ही नहीं आश्चर्य की बात है। मंत्री वर्मा ने कहा कि यदि ऐसा हुआ है तो विभागीय जांच कराएंगे। बघेल ने कहा कि मंत्री के खिलाफ कोई अफसर जांच नहीं कर सकता इसकी सदन समिति से जांच कराएं। वर्मा ने जवाब दिया हम विभागीय जांच कराएंगे। बघेल ने कहा जो अफसर जमीन की अफरा-तफरी कर रहे हैं वो मंत्री की जांच कैसे करेंगे। इतना बड़ा लैंड स्केम हो गया और मंत्री को पता नहीं।

जलाशय की जमीन का लैंड यूज बदल गया, जमीन की ट्रांसफर कर दी गई। कैबिनेट मंत्री को न पता है न अनुमति है। इसलिए कह रहा हूं विधानसभा की समिति से जांच करा लें। श्री बघेल ने कहा मध्यप्रदेश का मड़वा ताल जमीन घोटाले के बाद तय हुआ था कि लैंड यूज राजस्व मंत्री की कमेटी ही बदलेगी। और यहां उल्टा ही हो गया। इसमें मंत्री को जानकारी न होना और भी संदिग्ध है। राजस्व मंत्री वर्मा ने विधानसभा की समिति के बजाए विभागीय जांच कराने की बात कहते रहे। इसका विरोध करते हुए भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने सरकार विरोध नारेबाजी शुरू कर दी। वे सदन कमेटी से जांच कराने, जमीन घोटाला बंद करने के नारे लगाते हुए सदन से बाहर हो गए।

रायपुर में जिला पंचायत चुनाव की तारीख फिर बदली

■ **कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट में किया जोरदार प्रदर्शन, कहा- बहुमत नहीं इसलिए टल रहा चुनाव**

रायपुर। रायपुर जिला पंचायत चुनाव की तारीख बार-बार बढ़ाए जाने के विरोध में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

कांग्रेस के संयुक्त महासचिव विनोद तिवारी ने बताया कि 23 फरवरी को तीसरे चरण का चुनाव संपन्न होने के बाद 5 मार्च को जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की घोषणा की गई थी। हालांकि, प्रशासन ने 3 मार्च को चुनाव की तारीख बदलकर 12 मार्च कर दी। इसके बाद, आज 12 मार्च को चुनाव को फिर स्थगित कर 20 मार्च की नई तारीख घोषित कर दी गई।

चुनाव स्थगित किए जाने की सूचना मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्र हुए

और जमीन पर बैठकर घंटों विरोध प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन के दौरान एडीएम रायपुर ने कांग्रेस नेताओं से चर्चा कर उन्हें आगामी चुनाव तिथि से अवगत कराया और समय पर चुनाव कराने का आश्वासन दिया।

विनोद तिवारी ने भाजपा पर चुनाव में धांधली की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा के पास जिला पंचायत में बहुमत नहीं है, इसलिए वे बार-बार चुनाव की तारीख बढ़ा रहे हैं ताकि किसी तरह जोड़-तोड़ कर अपना अध्यक्ष बना सकें। लेकिन कांग्रेस के पास बहुमत है, इसलिए भाजपा घबराई हुई है।

राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन में ज्योतिष काउंसिल गठन की मांग

रायपुर। आशीर्वाद भवन, रायपुर में कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन में देशभर के 20 शहरों से आए 50 से अधिक विद्वान ज्योतिषाचार्यों ने भाग लिया। सम्मेलन में ज्योतिष, वास्तु एवं अंक विज्ञान को सुव्यवस्थित जीवन जीने का मार्गदर्शक बताया गया।

कार्यक्रम में रायपुर की प्रतिष्ठित हस्तियां, पं. लक्ष्मीकांत शर्मा (देव पंचांग), शिक्षाविद् पं. विष्णु प्रसाद शास्त्री और उज्जैन से पं. ईश्वर चंद्र दुबे ने अपने विचार प्रस्तुत किए। महाकाल धाम अमलेश्वर के संस्थापक पं. प्रियाशरण त्रिपाठी, पराशरीय ज्योतिष संस्थान के पं. प्रफुल्ल दुबे और अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति के अध्यक्ष एस्ट्रो पं. योगेश तिवारी ने भी कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया।

कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पं. अरुण शुक्ल ने सम्मेलन में कहा कि विद्वान पंडितों की उपस्थिति के बावजूद कंप्यूटर और अल्पज्ञान वाले पंडितों की वजह से अच्छे रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था 14 वर्षों से वैवाहिक पत्रिका प्रकाशित कर रही है, जिसमें 800-1000 बायोडाटा प्रकाशित होते हैं, लेकिन मात्र 25-

40% रिश्ते ही तय हो पाते हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने सरकार से ज्योतिष काउंसिल के गठन की मांग की, जिससे ज्योतिष कार्य केवल पंजीकृत विद्वानों द्वारा किया जा सके। इस संबंध में हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन शासन को सौंपने की तैयारी की गई।

मुंबई से आए हितेश भाई गुरुजी ने दस महा विधाओं पर प्रकाश डाला, जबकि डॉ. हिना बेन जोशी ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन और पितृ दोष निवारण पर जानकारी दी। मुंबई की डॉ. साची केशरी ने टैरो कार्ड और राहु ग्रह के प्रभावों पर विशेष उद्बोधन दिया। रायपुर, बिलासपुर, उज्जैन, बीकानेर, कोरबा, और मुंबई सहित विभिन्न शहरों से आए विद्वानों ने ज्योतिष से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार प्रस्तुत किए। सम्मेलन में कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज और अन्य संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे।

ई-वे बिल जांच के नाम पर अवैध वसूली का मामला सदन में उठा

अनुज शर्मा ने उठाया मुद्दा, मंत्री ओपी चौधरी बोले, वसूली का आरोप गलत

रायपुर। ई-वे बिल जांच के नाम पर वसूली का मामला भाजपा विधायक अनुज शर्मा ने ध्यानाकर्षण के जरिए सदन में उठाया। अनुज शर्मा ने कहा कि ई-वे बिल के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि जांच के नाम पर अवैध वसूली की कोई शिकायत नहीं मिली है।

भाजपा विधायक अनुज शर्मा ने ई-वे बिल के नाम पर गाड़ियों को रोका जाता है, लेकिन लेन देन कर छोड़ दिया जाता है। व्यवसाइयों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि जांच के नाम पर अवैध वसूली की कोई शिकायत नहीं मिली है। एप के जरिए वाहनों की जांच की जाती है। बिल नहीं पाये जाने पर विभाग के अधिकारियों को वीडियो अपलोड कर व्हाट्स एप पर सूचना दी जाती है। 31 करोड़ को शास्ति वसूल की गई।

मंत्री ने बताया कि विभाग द्वारा चुनिंदा

अधिकारियों की एक ही जगह पर ड्यूटी नहीं लगाई गई है। पूरे प्रदेश में ई वे बिल जांच के लिए 15 टीमों का गठन किया गया है। 63 अधिकारी ई-वे बिल की जांच कर रहे हैं। कर अपवंचन करने वाले लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई की जाती है। कर अपवंचन रोकने विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है। कारोबारियों से अवैध वसूली नहीं की जाती है।

अनुज शर्मा ने कहा कि बिना ई-वे बिल के समान भेजने वाले कारोबारियों के खिलाफ़ क्या कार्रवाई की जाती है? मंत्री ने बताया कि कोई भी कारोबारी एप के जरिए दो मिनट के भीतर ई-वे बिल जारी कर सकता है। किसी भी टोल पर ऐसी गाड़ी आसानी से स्कैन हो जाती है। भारत सरकार का सॉफ्टवेयर बीफा है, जिसके जरिए आसानी से ट्रैकिंग की जा सकती है। ई-वे बिल जारी करने की लिमिट पचास हजार रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया है।

भाजपा विधायक अनुज शर्मा ने पूछा कि ई-वे बिल जारी कर कारोबार करने वाले कितने कारोबारियों के खिलाफ़ कार्रवाई की गई? इस पर मंत्री चौधरी ने कहा कि टैक्स वसूली के लिए टेरर क्रिएट करना उद्देश्य नहीं होता है। सॉफ्टवेयर में फ्लैश होने पर कार्रवाई की जाती है। जो ट्रांसपोर्ट करता है, प्रारंभिक जिम्मेदारी उसकी होती है। हमने करीब सौ के आसपास सीमित संख्या में रेड की कार्रवाई की है।

सीएम साय ने बस्तर पंडुम 2025 के प्रतीक चिन्ह का किया विमोचन

बुधवार से लोककला और परंपराओं का भव्य प्रदर्शन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के समिति कक्ष में आज बस्तर पंडुम 2025 के प्रतिक चिन्ह का विमोचन किया। इस आयोजन के माध्यम से बस्तर संभाग की समृद्ध लोककला, रीति-रिवाज, पारंपरिक जीवनशैली और सांस्कृतिक विरासत को संजोने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम, केदार कश्यप, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह विधायक लता उसेंडी, विधायक विनायक गोयल उपस्थित रहे।

आज से बस्तर पंडुम 2025 का भव्य आगाज होने जा रहा है। यह महोत्सव न केवल बस्तर के प्रतिभाशाली कलाकारों को एक मंच प्रदान करेगा, बल्कि उनकी कला को नई पहचान और प्रोत्साहन भी देगा।

7 प्रमुख विधाओं पर केंद्रित होगा आयोजन

''बस्तर पंडुम 2025'' में जनजातीय नृत्य, गीत, नाट्य, वाद्ययंत्र, पारंपरिक वेशभूषा एवं आभूषण, शिल्प-चित्रकला और जनजातीय व्यंजन एवं पारंपरिक पेय से जुड़ी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। ये स्पर्धाएं तीन चरणों में संपन्न होंगी।

जनपद स्तरीय प्रतियोगिता 12 से 20 मार्च, जिला स्तरीय प्रतियोगिता 21 से 23 मार्च, संभाग स्तरीय प्रतियोगिता दंतेवाड़ा में 1 से 3 अप्रैल तक सम्पन्न होगी। प्रत्येक स्तर पर प्रतिभागियों को विशेष पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे।

परंपराओं का भव्य प्रदर्शन

इस महोत्सव में बस्तर की पारंपरिक नृत्य-शैली, गीत, रीति-रिवाज, वेशभूषा, आभूषण और पारंपरिक व्यंजनों का शानदार प्रदर्शन होगा। प्रतियोगियों के प्रदर्शन को मौलिकता, पारंपरिकता और प्रस्तुति के आधार पर अंक दिए जाएंगे। आयोजन में समाज प्रमुखों, जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ नागरिकों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। प्रतियोगिता के विजेताओं के चयन के लिए एक विशेष समिति बनाई गई है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ आदिवासी समाज के वरिष्ठ मुखिया, पुजारी और अनुभवी कलाकार शामिल रहेंगे। इससे प्रतियोगिता में पारदर्शिता बनी रहेगी और पारंपरिक लोककला को न्याय मिलेगा।

बस्तर की संस्कृति को सहेजने का सुनहरा अवसर

''बस्तर पंडुम 2025'' सिर्फ एक महोत्सव नहीं, बल्कि बस्तर की गौरवशाली संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने तथा उन्हें वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने का प्रयास है। यह आयोजन बस्तर के कलाकारों के लिए सुनहरा अवसर है, जिससे वे अपनी कला और परंपराओं को संरक्षित करने के साथ-साथ एक नई पहचान भी बना सकेंगे। छत्तीसगढ़ की अनमोल विरासत को जीवंत रखने का यह महोत्सव प्रत्येक नागरिक के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव रहेगा।

संघर्षपूर्ण जीवन जीता है लोक कलाकार : विजय मिश्रा

रायपुर। सूरज ट्रस्ट के बैनर तले अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भरथरी गायिका सूरज बाई खांडे स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। मोती बाग प्रेस क्लब के सभागार में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक क्रांति लाने वाली संस्था चंदैनी गोंदा के प्रथम उद्घोषक डॉ सुरेश देशमुख थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ी लोक कलाओं में आ रही विकृति के प्रति चिंता व्यक्त की तथा नई पीढ़ी को सचेत किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ लोक हिंदी रंगकर्मी विजय मिश्रा अमित ने भरथरी गायिका सूरुज खांडे के जीवन में आए उतार-चढ़ाव की अभिव्यक्ति दी। उन्होंने कहा लोक कलाकार का जीवन संस्कृति- संस्कारों के लिए समर्पित होता है, किन्तु सदैव संघर्षपूर्ण रहता है।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर संभाग क्र.-1, रायपुर

मैनुअल पद्धति से निविदा आमंत्रण सूचना

विज्ञप्ति क्रमांक 1563/ एन.आई.टी.-21/टी.सी./ 24-25 रायपुर, दिनांक 10/03/2025

क्र.	कार्य का विवरण	अनुमानित राशि (लाख में)
1	Dismantelineg of Tahsil Office at Shashtri Chowk Raipur cg	5.15

2. **निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि- 24.03.2025**
उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही यह जानकारी विभागीय वेबसाईट www.cg.nic.in/pwdraipur/ में Live Tender के अन्तर्गत निविदा प्रपत्र में उपलब्ध। इनका अवलोकन संबंधित संभाग कार्यालय में किया जा सकता है।

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.-1
रायपुर

जी-242505893/3

सीरिया में अब कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है?

अभिनय आकाश

साहिर लुधियानवी साहब लिख गए हैं कि जंग तो खुद ही एक मसअला है, जंग क्या मसअलों का हल देगी। दुनियाभर के हुक्मरान इस बात को समझने को तैयार नहीं हैं। दो देशों के बीच जंग चल रही होती है कि तभी किसी दूसरे कोने से वॉर की खबरें आने लगती हैं। इन खबरों में अब सीरिया की एंट्री हुई है। एक मुल्क जिसे कभी अरब दुनिया का दिल कहा जाता था। जिसकी राजधानी दमिश्क की गलियों में तारीख की गूंज थी। उस मुल्क में आज ऐसी हुकूमत चला रही है, जिस पर उसी देश के सैकड़ों लोगों को मारने का आरोप लग रहा है। सीरिया में पिछले पांच दिनों से बशर अल असद के लड़ाकों और नई हुकूमत के दरमियान खूनी झड़पें शुरू हुई हैं। इस जंग का केंद्र सीरिया के तटवर्तीय इलाके लताकिया और तारतूस हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि सीरिया में क्यों हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा, कौन हैं वो लोग जो इस जंग को हवा दे रहे हैं। सबसे अहम सीरिया में आगे क्या होगा? सीरिया में वशर अल-असद की सत्ता खत्म होने के बाद अलावी समुदाय हिंसा का शिकार हो गया है। सीरिया के शहरों लटाकिया और टार्टस में 6 मार्च को हिंसा शुरू हुई, जब सीरिया की नई सरकार ने असद समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई की। यूके वेस्ड सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताविक, इस संघर्ष में 5 दिन के अंदर 973 लोगों की हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों और वीडियो के मुताबिक सुरक्षा बलों और सीरियाई अंतरिम सरकार के वफादार हथियारबंद लड़ाकों ने लोगों को मौत के घाट उतारा और इन हत्याओं से देश को शुद्ध करने की बात कही। सीरिया की नई सरकार ने सैन्य अभियान खत्म करने का ऐलान किया और इसे असद सरकार के वफादारों के विद्रोह को दवाने का अभियान बताया। लटाकिया के एक निवासी ने वताया, सशस्त्र लोग घर-घर जाकर कत्ल कर रहे थे। यह उनके लिए मनोरंजन जैसा था। एक अन्य निवासी वशीर ने वताया कि उनके चाचा, जो इतिहास के प्रोफेसर थे, और उनकी पत्नी को उनके घर में मार दिया। असद परिवार ने 50 साल में जितने अपराध किए, 3 महीनें में सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा की सरकार ने उतना ही अन्याय कर दिया है। बशर अल असद, अलावी समुदाय से थे, 50 साल तक सीरिया पर शासन किया। पिछले साल दिसंबर में सत्ता से हटाए गए। तब से देश में अस्थिरता है। नई सरकार में सुन्नी इस्लामी लड़ाके शामिल हैं, उन्होंने सभी समुदायों के समान हक का वादा किया, हिंसा ने उनके दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल एक विडियो में एक लड़ाका कहता है, यह आजादी की जंग थी, अब शुद्धिकरण की लड़ाई है। एक शख्स कहता है, अलावियों, हम तुम्हें, तुम्हारे बाप-दादाओं को मारने आ रहे हैं। एक विडियो में एक व्यक्ति को जबरदस्ती कुत्ते की तरह भौंकने के लिए कहा गया, फिर गोली मार दी गई। सीरिया पिछले 14 साल से गृहयुद्ध की आग में जल रहा है। पिछले साल दिसंबर में इस्लामी समूह हयात तहरीर अल-शाम (एटटीएस) के नेतृत्व में विद्रोही गुटों ने असद सरकार को सत्ता से हटा दिया था। असद को रूस भागना पड़ा और एक नई अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली है। नई सीरियाई सरकार ने कहा है कि वे असद समर्थकों के हमलों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार ने इस हिंसा के लिए पर्सनल ऐक्शन को जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि वे स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हिंसा ने सीरिया के तटीय क्षेत्रों, विशेष रूप से लताकिया और वनियास जैसे शहरों में भारी तवाही मचाई है। सड़कों पर शव पडे हैं और घर जला दिए गए हैं। हजारों लोग पहाड़ों की ओर भाग गए। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, सीरिया के अलावी लोगों ने भारत से मदद मांगी है। सीरिया की आबादी में सुन्नी मुसलमानों की संख्या लगभग 70-75 प्रतिशत है। बशर अल-असद खुद अलावी हैं। ऐसे में उनकी सरकार के पतन के बाद अलावी समुदाय का शिकार किया जा रहा है। सीरिया की सत्ता पर काबिज सशस्त्र गुटों ने असद शासन के अवशेषों को मिटाने के नारे के तहत सामूहिक हत्याएं, घरों पर आक्रमण और जबरन विस्थापन किया है।

राजनीति की आंधी में कांपता हिंदी का दीया

कुमार दिनेश

मार्च 2025 के पहले सप्ताह में जब तमिलनाडु की डीएमके सरकार हिंदी और हिंदीभाषियों पर भौतिक-राजनीतिक हमले तेज कर रही हो, तब हिंदीभाषी समुदाय का लगभग उदासीन और अन्तर्विभाजित पड़े रहना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

दो साल पहले तमिलनाडु में हिंदीभाषी मजदूरों-कामगारों पर राज्यभर में चाकू-कुल्हाडी से जानलेवा हमले की घटनाएं हुई थीं। उसमें 50 से अधिक लोग घायल हुए थे, दो की हत्या हुई और इन घटनाओं से डरे हिंदीभाषी कई दिनों तक जहाँ रह रहे थे, वहाँ मकान से बाहर नहीं निकले थे। लोग देवी-देवता और छठी मइया से रिजर्वेशन नहीं, जीवित घर लौटने भर की मनौती मांग रहे थे। उस समय वहाँ सत्तारूढ़ दल के समर्थक तमिलों ने रोजगार छीनने का आरोप लगाकर बिहार-यूपी के हिंदीभाषी मजदूरों-कामगारों पर हमले किये थे। अब केद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के जरिये तमिलों पर हिंदी थोपने का आरोप लगाकर माहौल बिगाड़ा जा रहा है।

दक्षिण भारत , विशेषकर तमिलनाडु में नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा नीति लागू करने के विरुद्ध राजनीतिक दुराग्रह का निशाना हिंदी को बनाया जा रहा है, जबकि भारत की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 676 जिलों के जनप्रतिनिधियों के सुझाव पर विचार कर बनी नई शिक्षा नीति-2020 (एनईपी) में सभी 22 भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने का पूरा ध्यान रखा गया है।

नई शिक्षा नीति 1968-1986 की शिक्षा नीति की अपेक्षा अधिक समावेशी है, फिर भी हिंदी-संस्कृत को लेकर तमिलनाडु के सत्तारूढ़ दल का दुराग्रह कम नहीं हुआ है। अब छात्र कोई भी दो भारतीय भाषाएं पढ सकते हैं, हिंदी, कन्नड़ या तमिल , यानी किसी भाषा को पढना किसी के लिए अनिवार्य नहीं है। यह उदारता तमिलनाडु के भाषाई चरमपंथियों को चुभ रही है, वे इसे हिंदी थोपना बता रहे हैं। भाषा के इस प्रकरण को वहां की डीएमके सरकार केंद्र की मोदी सरकार से टकराव का नया मुद्दा बना रही है।

सवाल यह है कि जब डीएमके शासित तमिलनाडु में हिंदी और हिंदीभाषियों पर सीधे हमले हो हैं, तब कांग्रेस नेतृत्व वाले 26 दलीय इंडी गठबंधन में इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों है? डीएमके प्रमुख स्टालिन के आपत्तिजनक बयानों की अनसुनी करना हिंदीपट्टी में जनाधार का दावा करने वाले कांग्रेस, राजद, सपा जैसे दलों के लिए सुविधाजनक क्यों है? जाहिर है, कि जैसे हिंदू कोई वोट बैंक नहीं है, हिंदू आस्था का अपमान कोई कॉमेडियन भी कर सकता है, कोई नेता महाकुम्भ को %फालतू% कह सकता है, वैसे ही भाषा के तौरपर हिंदी कोई वोट बैंक नहीं है, इसलिए इस वोट-दरिद्र भाषा का अपमान किया जा सकता है। तमिलनाडु को हिंदीभाषियों की वोट-दरिद्रता और भाषाई दर्पहीनता का पता है, इसलिए वहाँ बार-बार आघात हो रहे हैं।

परिवारवादी डीएमके में करुणानिधि की विरासत पाकर मुख्यमंत्री बने स्टालिन ने त्रिभाषा फार्मूले और नई शिक्षा नीति के विरुद्ध जो सर्वदलीय बैठक बुलाई है, उसमें कांग्रेस सहित 45 दलों को आमंत्रित किया गया है, लेकिन केवल भाजपा ने इसके बहिष्कार की घोषणा की। क्या बाकी दलों को अपने हिंदीभाषी जनाधार के सम्मान की रक्षा में कुछ नहीं बोलना चाहिए? यदि राजनीतिक हलके में स्टालिन के हिंदी-विरोधी बयानों पर राहुल गांधी , लालू प्रसाद, अखिलेश यादव आदि चुप हैं, तो कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन भाषा -शिक्षा , पत्रकारिता और साहित्य के उत्तर भारतीय क्षितिज से भी हिंदी की अस्मिता के पक्ष में कोई स्वर नहीं फूटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है ।

दरअसल, इस अराजनीतिक दिखते सन्नाटे के पीछे है हिंदी की बोलियों को भाषा का दर्जा दिलाने की मीठी राजनीति (साफ्ट पालिटिक्स) करने में लगे समूह या संगठन। जैसे , जातीय जनगणना की राजनीति हिंदू अस्मिता को विरल करती है, उसी तरह बोलियों की सियासत 55 करोड़ लोगों के विशाल हिंदीभाषी समुदाय को बाँट-छांट कर छोटा करने पर तुली है।

जब हिंदी की मीठी आंचलिक बोलियों (डायलेक्ट) को अलग भाषा (लैंग्वेज) या मातृभाषा बताने का आग्रह सुनियोजित तरीके से बढाया जाएगा, तब हिंदी किसी की भाषा नहीं रहेगी, हिंदीभाषी अल्पसंख्यक हो जाएँगे। हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने का सपना धरा रह जाएगा। तमिलनाडु यही चाहता है, इसलिए स्टालिन आरोप लगा रहे हैं कि हिंदी दक्षिण भारत की भाषाओं के लिए ही नहीं, उत्तर भारत की भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली, अवधी, बुंदेलखंडी जैसी भाषाओं के लिए खतरा है।

इधर यूपी-बिहार में लोग अपनी आंचलिक बोलियों को मातृभाषा बताने की मुहिम चला कर स्टालिन का परोक्ष समर्थन ही कर रहे हैं। ऐसे में हिंदी किसी की मातृभाषा नहीं रह जाएगी। भाषा राजनीति की आंधी में कांप रहा है हिंदी का दीया । लगभग 200 हिंदीभाषी सांसदों, हिंदी के विकास में लगे दर्जनों संगठनों, हिंदी साहित्य सम्मेलन, अन्तरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय या राष्ट्रभाषा परिषद जैसे किसी संगठन -संस्थान ने तमिलनाडु के हिंदी-संस्कृत विरोधी नरेटिव के विरुद्ध कोई टिप्पणी नहीं कर जो उदासीनता दिखाई, वह आत्मघाती है। विचलित करने वाली यह स्थिति बदलनी चाहिए।

तमिलनाडु की भाषाई असहिष्णुता और हिंसक घटनाओं के विरुद्ध दिल्ली के जंतर-मंतर पर या हिंदीभाषी प्रदेशों की राजधानी में हिंदी समर्थक महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने भी कोई मोमबत्ती जलाने नहीं आया! हिंदी वालों ने हर काम सरकारों और नेताओं के भरोसे छोड़ दिया है। हिंदी दिवस मनाने वाले भी पूरे परिदृश्य से गायब हैं। विडम्बना देखिये कि असम , केरल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु में जो लोग हिंदीभाषी पहचान के कारण मारपीट का शिकार होते हैं, उन्हें बिहार-यूपी लौटने पर अपने घर में भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका भाषी पहचान प्रिय है। हिंदीभाषी राज्यों में भाषा-बोली के विकास के लिए नहीं, बल्कि केवल वोट की राजनीति के लिए बोलियों को भाषा मानकर जो अकादमियाँ बनायी गईं, वे आज हिंदीविरोधी राजनीति की ही धार तेज कर रही हैं। आज वह हिंदी संकट में है, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनकी परम्परा के साहित्यकारों-पत्रकारों ने गांव-देहात से उठा कर विमर्श ,आलोचना, विज्ञान, न्याय , विधेयन , अनुसंधान, जनसंचार और शासन की भाषा बनने की शक्ति प्रदान की। क्या इस राजपथ से हम हिंदीभाषियों को खेत की मेड़ और चौपालों में लौट जाना चाहिए? इस पूरे प्रकरण पर व्यापक विमर्श होना चाहिए।

एकात्मता के स्वर — पुराण

भारतीय संस्कृति के मूलाधार के रूप में वेदों के बाद पुराणों का ही स्थान है। वेदों में वर्णित अगम रहस्यों तक जनसामान्य की पहुँच नहीं हो पाती, परंतु पुराणों की मंगलमयी, ज्ञानप्रदायिनी दिव्य कथाओं का श्रवण-मनन और पठन-पाठन करके जन-साधारण भी भक्तितत्त्व के अनुपम रहस्य से सहज परिचित हो सकते हैं। महाभारत में कहा गया है पुराणसंहिता: पुण्या: कथा धर्मार्थसंश्रिता:। आदि. प. 1/16 अर्थात पुराणों की पवित्र कथाएँ धर्म और अर्थ को प्रदान करने वाली हैं। श्रीमद्भागवत में इतिहास पुराणनि पंचमं वेदमीश्वर: । सर्वेभ्य एवं वक्त्रेभ्य: संसृजे सर्वदर्शन:।। 3/12/36 कहा है कि इतिहास और पुराणरूप पाँचवें वेद को समर्थ, सर्वज्ञ ब्रह्मा जी ने अपने सभी मुखों से प्रकट किया है। इसलिए कहा है पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्। इनका विस्तार सौ करोड़ श्लोकों का माना गया है। कम आयु में इतना पढ़ना असम्भव जान द्वापर के अंत में श्रीकृष्ण द्वैपायन व्यास ने इसे अठारह भागों में बाँटकर तदथाऽत्र चतुर्लक्षं संक्षेपेण निवेशितम् ।। मत्स्यपुराण 53/11 चार लाख श्लोकों में सीमित कर दिया। कहते हैं कि स्वर्गादि लोकों में आज भी एक अरब श्लोकों का विस्तृत पुराण है। महर्षि व्यास वास्तव में इनके रचियता नहीं, अपितु संक्षेपक या संग्राहक ही सिद्ध होते हैं। इसलिए वेदों की भांति पुराण भी अनादि माने जाते हैं। निरूक्त की व्याख्यानुसार- पुराणमाख्यानं पुराणं यानी जिसमें पुरातन आख्यान हो वह पुराण है। एक अन्य व्याख्यानुसार पुराऽपि नवम् पुराणम् यानी जो पुराना होने पर नवीन हो वह पुराण है। देवी भागवत के अनुसार श्रुति और स्मृति दोनों ही नेत्र हैं और पुराण हृदय हैं। पुराणों की संख्या अठारह है। अब पुराणों के नाम व वर्णित श्लोकों की संख्या बतलाता हूँ। 1. ब्रह्मपुराण-तेरह हजार श्लोक, 2 पद्मपुराण- पचपन हजार, 3 वैष्णव (विष्णुपुराण) - तेईस हजार, 4. वायवीय (वायुपुराण या शिवपुराण)- चौबीस हजार, 5. भागवत पुराण -अठारह हजार, 6. नारदीय (नारदपुराण)- पच्चीस हजार, 7. मार्कण्डेयपुराण- नौ हजार, 8 आग्नेय (अग्निपुराण)- सोलह हजार, 6. भविष्य पुराण- चौदह हजार पाँच सौ, 10. ब्रह्मवैवर्तपुराण- अठारह हजार, 11. लैंग (लिंगपुराण)- ग्यारह हजार, 12. वराहपुराण- चौबीसहजार, 13. स्कन्धपुराण- इक्यासी हजार एक सौ, 14. वामनपुराण-दश हजार, 15. कूर्मपुराण- अठारह हजार, 16. मत्स्यपुराण- चौदह हजार, 17. गरुड़ पुराण- उन्नीस हजार तथा 18. ब्रह्माण्डपुराण- में बारह हजार दो सौ श्लोक हैं। इन प्रमुख पुराणों से कुछ उपपुराण भी निर्मित हुए हैं। जैसे- नरसिंहपुराण, नन्दीपुराण, साम्बपुराण, आदित्यपुराण आदि।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

(गतांक से आगे...)

श्रीमद्भागवत (12।7।6) में इन्हीं पांच विषयों को प्रपंचित करके पुराण के विषयों की दश संख्या दी है। तथा अग्नि पुराण में मन्त्रशास्त्र एवं सामुद्रिकशास्त्र को भी पुराण विषयों में परिगणित किया है। तात्पर्य यह है कि नुख्यतया य पाँच विषय तो सर्वत्र समानरूप से ही वर्णित हैं, परन्तु पाठकों के बुद्धिवैशद्य के लिये श्री वेदव्यास जी ने कहीं 2 इन्हीं पाँचों के अन्तर्भूत अन्य विषयों का पृथक् 2 भी परिगणन कर दिया है, जो लाघव गौरव भेद से उभयथा सुव्यवस्थित है। तथापि हम यहां मुख्य विषयों का ही प्रतिपादन करेंगे।

सर्ग- अव्याकृतगुणक्षोभान्महतस्त्रिवृतोऽहम:। भूतमात्रेन्द्रियार्थानां संभव: सर्ग उच्चते।। (श्रीमद्भागवत 12। 7।11)

अर्थात् - जिसमें विशेष आकार नहीं विद्यमान था- ऐसे साम्या-वस्थापन्न प्रधान-तत्त्व के तीनों गुणों के क्षोभ से महत्तत्व और उससे अहंकार तथा अहंकार से पञ्चभूतमात्राओं, सूक्ष्म इन्द्रियों और तदधिष्ठात्री देवताओं की उत्पत्ति को सर्ग कहते हैं।

अहिन्दू मत मतान्तर- यह दृश्य जगत् किन 2 तत्त्वों से बना है? तथा उक्त तत्त्वों का पौर्वापर्य क्या है? यह रहस्य पुराणों को छोड़कर संसार के दूसरी किसी धर्म पुस्तक में ढूंढने पर भी नहीं मिल सकता। मौलाना साहिब कुरान शरीफ के तीन सौ साठ सपारों के सहस्र पाठ कर डालें, मंजिलों में मगजपच्ची करें और आयतों के ताने बाने में तन्मय हो जाएं फिर भी सृष्टि के आदिम तत्त्वों की छाया उन्हें न मिल सकेगी। पादरी साहिब तेंतीस दफै, %तौरेत% को और बाणवें बार बाईबिल को तथा अगणित बार अश्लील को घोट 2 कर पीजाएं तब भी सृष्टि के श्रादिम तत्त्वों का पता न पा सकेंगे। यही दशा जैन बौद्ध पारसी और दयानन्दी आदि मतमतान्तरों की है।

क्रमश: ...

होलिका दहन

श्वेता सिंह

हिंदू पंचांग के अनुसार, फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है, और अगले दिन धुलंडी मनाई जाती है। इस दिन लोग एक-दूसरे को रंग-गुलाल लगाकर, गले मिलकर होली खेलते हैं और पुराने गिले-शिकवे दूर करते हैं। होलिका दहन 2025 का आयोजन इस साल विशेष रूप से महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि भद्रा की स्थिति के कारण होलिका दहन के लिए निर्धारित समय में कुछ बदलाव हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार, भद्रा के दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना मना होता है, और होलिका दहन में भी इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है।

होलिका दहन 2025 का शुभ मुहूर्त

2025 में होलिका दहन का समय 13 मार्च को रात 11 बजकर 26 मिनट से लेकर 14 मार्च को रात 12 बजकर 30 मिनट तक रहेगा। इस समय के बीच ही होलिका दहन करना शुभ रहेगा, क्योंकि भद्रा की अवधि 11 बजकर 26 मिनट तक रहेगी, उसके बाद दहन करना शुभ होगा।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, भद्रा के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि इसे नकारात्मक प्रभाव से जोड़कर देखा जाता है। इस बार भद्रा के कारण होलिका दहन का समय सीमित हो जाएगा, लेकिन इसके बाद का समय काफी शुभ है। इसलिए, होलिका दहन करने के लिए 13 मार्च की रात को 11 बजकर 26 मिनट के बाद का समय ही सबसे उपयुक्त होगा।

पूर्णिमा तिथि प्रारंभ : 13 मार्च, गुरुवार- सुबह 10:35 बजे

पूर्णिमा तिथि समाप्त : 14 मार्च, शुक्रवार - दोपहर 12:23 बजे

होलिका दहन की पूजन विधि

गाय के गोबर से होलिका और प्रह्लाद की मूर्ति बनाकर थाली में रखें। रोली, फूल, मूंग, नारियल, अक्षत (चावल), साबुत हल्दी, बताशे, कच्चा सूत, फल, और एक जल से भरा कलश रखें। भगवान नरसिंह का ध्यान करके रोली, चंदन, पांच प्रकार के अनाज और फूल अर्पित करें। कच्चा सूत लेकर होलिका की सात बार परिक्रमा करें। गुलाल अर्पित करें और जल चढ़ाकर पूजा समाप्त करें।

इन कार्यों से बचें

इस दिन किसी से झगड़ा या कटु वचन बोलने से बचें, क्योंकि यह आपके आत्मिक शांति को प्रभावित कर सकता है। इस दिन किसी को अपमानित करने से पाप लगता है, और इससे आपके जीवन में नकारात्मकता आ सकती है। इस दिन शराब, मांसाहार और किसी भी प्रकार के नशे से संबंधित चीजों का सेवन वर्जित होता है। यह मानसिक और शारीरिक शुद्धता के लिए आवश्यक है। घर और शरीर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, गंदे कपड़े पहनने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो सकती है और यह आपके मनोबल को प्रभावित कर सकता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, फाल्गुन पूर्णिमा की रात बाल धोना या कटवाना अशुभ माना जाता है, इसलिए इसे न करें।

सत्ता परिवर्तन: ट्रूडो के बाद कार्नी को कमान

केएस तोमर

वैश्विक स्तर पर चर्चित केंद्रीय बैंकर से कनाडा के प्रधानमंत्री तक का मार्क कार्नी का सफर नेतृत्व के नाटकीय बदलाव को दर्शाता है। बैंक ऑफ कनाडा एवं बैंक ऑफ इंग्लैंड में उनके कार्यकाल ने वित्तीय संकट मोचक की प्रतिष्ठा अर्जित की, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व की चुनौतियां बिल्कुल अलग हैं। उन्हें विरासत में एक खंडित राजनीतिक परिदृश्य मिला है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में तेजी से संरक्षणवादी बनते अमेरिका और भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों से निपटने की चुनौती है। उनकी आर्थिक सूझबूझ राजकोषीय नीति और व्यापार संबंधों के प्रबंधन में उन्हें विश्वसनीय बनाती है, लेकिन भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने, शत्रुतापूर्ण व्हाइट हाउस को संभालने और कनाडा की संस्थाओं में जनता का विश्वास बहाल करने जैसी चुनौतियों को देखते हुए उनकी असल परीक्षा कूटनीतिक होगी। उनकी नेतृत्व शैली यह निर्धारित करेगी कि क्या वह वैश्विक मंच पर कनाडा की स्थिति को स्थिर करने में सफल होते हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन त्रूदो ने कनाडा में भारतीय समुदाय के बहुसंख्यकों को नाराज कर दिया था, क्योंकि उन्होंने खालिस्तानियों का खुलकर समर्थन किया था, जो भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों के लिए जिम्मेदार थे। नए प्रधानमंत्री ने संकेत दिया है कि वह भारत के साथ मजबूत संबंधों के पक्षधर हैं, जो दोनों देशों के हित में है। नए प्रधानमंत्री को संबंधों को पटरी पर लाने के लिए अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करना होगा। वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार, कनाडा में भारतीय समुदाय की संख्या लगभग 18,58,755 है, जो राष्ट्रीय जनसंख्या का लगभग 5.1 फीसदी है। इस जनसांख्यिकी ने कनाडा के बहुसांस्कृतिक परिदृश्य को काफी प्रभावित किया है, खासकर टोरंटो, वैंकूवर, कैलगरी, एडमॉन्टन और मॉन्ट्रियल जैसे शहरी केंद्रों में। कनाडा की राजनीति में भारतीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है तथा शासन में उनके प्रतिनिधित्व के महत्व को उजागर करती है। लेकिन जून 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया में हुई सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद अक्तूबर, 2024 में कनाडा और भारत के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ गया। जस्टिन त्रूदो ने भारत सरकार पर कनाडा में हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगाया, जिसके चलते राजनयिकों को निष्कासित किया गया और द्विपक्षीय संबंधों में तनाव पैदा हुआ। इससे कनाडा स्थित भारतीय समुदाय के बीच चिंता पैदा हो गई, खासकर आव्रजन, शिक्षा और आर्थिक संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में।

नए प्रधानमंत्री को भारतीय समुदाय के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ना होगा। उनकी चिंताओं को संबोधित करना, समावेशी नीतियों को बढ़ावा देना और भारत के साथ राजनयिक संबंधों को सुधारने की दिशा में काम करना कनाडा के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने में इस जीवंत समुदाय की भलाई और निरंतर योगदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होंगे। कनाडा में समावेशी शासन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय समुदाय के योगदान को पहचानना और उसका मूल्यांकन करना आवश्यक है। नए प्रधानमंत्री को इस जीवंत समुदाय के साथ जुड़ने से सामाजिक सामंजस्य को मजबूत करने तथा ऐसी नीतियों को बढ़ावा देने के अवसर मिलेंगे, जो विविधता और समावेशन के प्रति कनाडा की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती हैं। कार्नी ने राजनीतिक मतभेदों के बीच कार्यभार संभाला है। लिबरल पार्टी के प्रति जनता का भरोसा कम हुआ है, खासकर पश्चिमी कनाडा में, जहां त्रूदो की नीतियों ने तेल-निर्भर प्रांतों को अलग-थलग कर दिया। इस बीच, दक्षिणपंथी लोकलुभावनवाद ने गति पकड़ी है। बेशक उन्हें चुनावी अनुभव नहीं है, लेकिन एक आर्थिक रणनीतिकार के रूप में उनकी विश्वसनीयता उन्हें मतदाताओं का विश्वास हासिल करने में मदद कर सकती है।

मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, ब्याज दरों को स्थिर करना और क्षमता संबंधी चिंताओं को दूर करना उनकी तत्काल प्राथमिकताएं होंगी। प्रभावी ढंग से शासन करने के लिए प्रगतिशील और रूढ़िवादी, दोनों मतदाताओं से समर्थन पाना महत्वपूर्ण होगा, जबकि पार्टी के भीतर और मध्यमार्गी मतदाताओं के बीच विश्वास बहाल करना उन्हें राजनीतिक दीर्घायु प्रदान करेगा। कार्नी को भारत के साथ संबंधों को सुधारने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीधी बातचीत शुरू करना तथा सार्वजनिक आरोपों से बचना होगा, क्योंकि इससे संबंधों में और अधिक कड़वाहट पैदा हो सकती है। कनाडा से संचालित खालिस्तान समर्थक उग्रवाद के बारे में भारत की चिंताओं का समाधान करना तथा भारत के साथ आतंकवाद-विरोधी सहयोग को मजबूत करना जरूरी है। भारत के रॉ और आईबी के साथ खुफिया जानकारी साझा करना, आतंकवादियों को वित्तपोषित करने या भारत के खिलाफ हिंसा भड़काने में शामिल लोगों को निर्वासित करने पर विचार करना, तथा चरमपंथी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए द्विपक्षीय सुरक्षा कार्यबल की स्थापना करना, भारत की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए कनाडा की प्रतिबद्धता का संकेत हो सकता है।

रुके हुए कनाडा-भारत व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर चर्चा फिर से शुरू करना और भारत के प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में कनाडाई निवेश को प्रोत्साहित करना, कनाडा के ऊर्जा और एआई उद्योगों में भारतीय निवेश को आकर्षित करना आगे बढ़ने के लिए एक रचनात्मक मार्ग प्रदान करेगा। भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए वीजा प्रतिबंधों से जुड़े मुद्दों को हल करना और शैक्षणिक व सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ाना संबंधों को मजबूत करेगा। कार्नी के सामने एक नाजुक संतुलन बनाने की चुनौती है- घरेलू राजनीतिक संवेदनशीलताओं का प्रबंधन करते हुए भारत के साथ विश्वास बहाल करना। हालांकि, उन्हें कनाडा में खालिस्तान समर्थक समूहों के राजनीतिक दबाव, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के आरोपों और त्रूदो के रुख का समर्थन करने वाले वामपंथी उदारवादियों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। यदि वह एक दृढ़, लेकिन संतुलित नीति लागू करते हैं (जिसमें सिख समुदाय की रक्षा करते हुए चरमपंथियों पर नकेल कसी जाए),?तो वह घरेलू अस्थिरता को बढ़ावा दिए बिना भारत-कनाडा संबंधों को सुधार सकते हैं।

आज का इतिहास

1848 प्रिंस क्लेमेन्स वॉन मेट्टर्टिच ने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के राज्य चांसलर और विदेश मंत्री के पद से इस्तीफा दिया।
1878 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कैंब्रिज यूनिवर्सिटी को अपने पहले गोल्फ मैच में हराया।
1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट प्रभाव में आया और अगले ही दिन अमृत बाजार पत्रिका अंग्रेजी समाचार पत्र बना।
1884 स्व-घोषित महदी मुहम्मदअहमद के प्रति निष्ठावान महदीवादी युद्ध-बलों ने संयुक्त आंग्ल-मिस्र बल का बचाव करते हुए सूडान में 319-दिवसीय घेराबंदी शुरू की।
1897 सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना की गयी।
1920 कप्प पुट्स ने वीमार गणराज्य सरकारफ्रॉम बर्लिन को कुछ समय के लिए हटा दिया।
1943 होलोकॉस्ट-नाज़ी जर्मन सैनिकों ने पोलैंड के क्राकोव में यहूदीगेटो को नष्ट करना शुरू कर दिया, जिससे प्लाज़्ज़ो लेबर कैंप (निर्वासित चित्र) पर काम करने में सक्षम लगभग 8000 यहूदियों को भेजा गया, बाकी को या तो अटैक किया गया या औशविट्ज़ को भेजा गया।
1943 प्रलय: नाजी जर्मन सैनिकों ने पोलैंड के क्राकोव में यहूदी यहूदी बस्ती को नष्ट करना शुरू कर दिया, लगभग 8, 000 यहूदियों ने प्लाज़्ज़ो श्रम शिविर में काम करने में सक्षम माना, बाकी या तो मारे गए या औशविट्ज़ को भेजे गए।
1944 इटली और सोवियत संघ ने एक दूसरे के साथ राजनयिक संबंध दुबारा बहाल किए।
1961 ब्रिटेन की दो महिला और तीन पुरुष अधिकारियों पर रूस के लिए जासूसी करने का आरोप लगा था। कहा गया था कि वो देश के सुराग रूस भेज रहे थे।
1961 भूस्खलन से सोवियत संघ में 145 लोगों की मौत हुई।
1962 अमेरिका के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष लिमन लेमनगिटेरडिलीवर ने रक्षा के सचिव रॉबर्ट मैकनामारा के एक प्रस्ताव का आह्वान किया, जो फिडेलकैस्ट्रो और क्यूबा के खिलाफ युद्ध के लिए सार्वजनिक समर्थन बनाने के लिए ऑपेरशन नॉर्थवुड्स है, जिसे अंतत: राष्ट्रपति जॉन एफ.केनेडी ने अस्वीकार कर दिया था।
1963 खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये अर्जुन पुरस्कार की घोषणा हुई।

आक्रमणकारियों से स्वयं को जोड़कर उनका गुणगान करना कितना स्वीकार्य?

बलबीर पुंज

क्या किसी भी सभ्य समाज के लिए मुगल आक्रांता औरंगजेब, तानाशाह हिटलर और गांधीजी का हत्यारा गोडसे गौरव हो सकते हैं? जब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र में विधायक अबू आसिम आजमी ने औरंगजेब का महिमामंडन किया, तब वह केवल अपना व्यक्तिगत मत ही प्रकट नहीं कर रहे थे। उनका वक्तव्य भारतीय उपमहाद्वीप में व्याप्त विषाक्त मानस का न केवल प्रतिनिधित्व कर रहा था, अपितु इसने हिंदू-मुस्लिम संबंधों में शताब्दियों से चले आ रहे तनाव के कारणों को भी कुरेद दिया। यह चिंतन ही समरसता, बहुलतावाद, पंथनिरपेक्षता व?सह-अस्तित्व युक्त समाज को सीधी चुनौती है। इसी मानसिकता के कारण भारत का रक्तरंजित विभाजन हुआ और पाकिस्तान-बांग्लादेश अस्तित्व में आए?

आजमी और उनके मानसबंधुओं के अनुसार, 'औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था। उसकी लड़ाई राजकाज के लिए थी, न कि मजहबी। उसने कई हिंदू मंदिर बनवाए।' इस्लामी बादशाहों की आत्मकथाओं और समकालीन इतिहासकारों द्वारा कलमबद्ध वृतांतों से स्पष्ट है कि आठवीं शताब्दी के बाद भारत में मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा तलवार के बल पर स्थानीय लोगों का धर्मांतरण, नरसंहार, शोषण, पूजास्थलों का विध्वंस और उनके मानबिंदुओं का अपमान-अपवित्रीकरण-इस्लामी दृष्टिकोण से गर्व योग्य कृत्य?थे। इसलिए औरंगजेब का 49 वर्षीय शासनकाल कोई अपवाद नहीं था। इतिहास ऐसे रक्तरंजित विवरणों से भरा है। इस्लामी दरबारी मोहम्मद साकी मुस्तैद खान ने मासिर-ए-आलमगीरी (1731) में लिखा था कि औरंगजेब ने फरमान जारी करके काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद का निर्माण करवाया, अन्य धर्मावलंबियों के जबरन धर्मांतरण का आदेश दिया, मथुरा स्थित केशवराय मंदिर को ध्वस्त किया और जोधपुर में कई मंदिरों के विध्वंस के बाद उनके अवशेषों को जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफना दिया।

क्या यह सच नहीं कि औरंगजेब ने इस्लाम नहीं अपनाने पर नौवें सिख गुरु तेग बहादुरजी और अन्य कई सिखों की हत्या करवाई, तो वीर छत्रपति संभाजी महाराज को अमानवीय यातनाएं देकर मारा? यदि मजहबी पक्ष छोड़ भी दें, तो एक व्यक्ति के रूप में औरंगजेब कैसा था? सत्ता-लिप्सा में जहां उसने अपने पिता शाहजहां को कैद किया, वहीं अपने तीनों भाइयों- दारा शिकोह, शाहशुजा और मुराद की निर्मम हत्या करवा दी। क्या ऐसा क्रूर-हृदयविहीन व्यक्तित्व किसी भी सभ्य समाज के लिए आदर्श हो सकता है? यह ठीक है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने अथाह संपत्ति लूटने के इरादे से भारत पर हमले किए, परंतु इनके पीछे मजहबी प्रेरणा भी थी। इतिहास में इसके कई प्रमाण हैं, जिनमें से एक वर्ष 1398 में भारत पर हमला कर हजारों-लाखों निरपराधों को मारने वाला तैमूर है। बकौल तुजुक-ए-तैमूरी? में तैमूर ने कहा था, 'मेरे हिंदुस्तान आने के दो उद्देश्य हैं। पहला-काफिरों से जिहाद करना और सवाब कमाना। दूसरा-काफिरों की दौलत लूटना, क्योंकि यह मुसलमानों के लिए मां के दूध की तरह जायज है।' सोचिए, देश के एक प्रसिद्ध फिल्मी परिवार ने अपने बेटे

का नाम तैमूर रखा है।

क्या इस्लामी आक्रांताओं और हिंदू-सिख शासकों में संघर्ष केवल सत्ता का था? इस पर दावा किया जाता है कि मुस्लिम शासकों के दरबारों में हिंदू और हिंदू-सिख शासकों के दरबारों में मुस्लिम थे। यदि इस कुतर्क को मानें, तो अंग्रेजों के लिए लड़ने वाले अधिकांश सैनिक और क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाने वाले कौन थे? जलियांवाला बाग में जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने वाले अंग्रेज नहीं थे। क्या यह कहना ठीक होगा कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम देश की आजादी के बजाय सत्ता का संघर्ष था? बार-बार दोहराया जाता है कि मुगलों ने मंदिरों का निर्माण करवाया। संभव है कि कुछ मामलों में ऐसा हो। परंतु क्या इससे उनके असंख्य अपराध मिट जाते हैं? आक्रामणकारी ब्रितानियों ने भी अपनी औपनिवेशिक रणनीति के अंतर्गत कुछ मंदिरों के निर्माण-जीर्णोद्धार होने दिए। वे देश में रेल और टेलीग्राफ लेकर आए, तो बिना किसी स्थानीय पूजास्थल को ध्वस्त किए भव्य भवनों का निर्माण करवाया। इन सबके बावजूद अंग्रेजों की भूमिका एक कुटिल विदेशी आक्रमणकारियों की थी, जिन्होंने भारत की प्रज्ञा और अगाध संपदा को बेदर्दी से नष्ट किया।

इस्लामी आक्रांताओं के यशगान में एक भ्रामक तर्क यह भी है कि यदि वे इतने ही क्रूर और मजहबी थे, तो देश में लाखों मंदिर और करोड़ों हिंदू कैसे बचे? मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारतीय उपमहाद्वीप से इस्लाम-पूर्व संस्कृति व उसके प्रतीकों को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसमें वे आंशिक रूप से सफल भी हुए। बीते एक हजार वर्षों में भारतीय उपमहाद्वीप के जिन क्षेत्रों में सनातन संस्कृति का ह्रास हुआ, वहां बहुलतावाद, पंथनिरपेक्षता व सह-अस्तित्ववाद ने दम तोड़ दिया। हिंदू-बौद्ध-सिख विहीन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश इसके ज्वलंत प्रमाण हैं। यदि खंडित भारत का हिंदू चरित्र आज भी अक्षुण्ण है, तो इसका श्रेय महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा सांगा, महाराजा छत्रसाल, सिख गुरुओं की परंपरा से लेकर अनेकों वीरों और साधु-संतों को जाता है, जिन्होंने भारत के अस्तित्व की रक्षा हेतु निरंतर प्रतिकार किया। क्या कोई बता सकता है कि उत्तर-पश्चिम भारत के शत-प्रतिशत प्राचीन मंदिर अपने मूल स्वरूप में क्यों नहीं हैं? यहां जो भी पुरातन पूजास्थल हम देखते हैं, उसके भवन सतत सांस्कृतिक पुनरुद्धार के कारण 200-250 वर्ष पुराने हैं।

जिस वैचारिक नींव पर पाकिस्तान खड़ा है, उसकी और मुस्लिम आक्रांताओं की प्रेरणा एक है। पाकिस्तानी स्कूली पाठ्यक्रमों में इस्लामी आक्रांता मुहम्मद बिन कासिम को 'पहला पाकिस्तानी', तो सिंध को पहला 'इस्लामी प्रांत' बताया जाता है, क्योंकि कासिम ने वर्ष 711-12 में हिंदू राजा दाहिर द्वारा शासित तत्कालीन सिंध पर हमला किया था। इसी मानसिकता के कारण पाकिस्तान में मिसाइलों-युद्धपोतों के नाम-गजनी, गौरी, बाबर, अब्दाली, टीपू सुल्तान को समर्पित हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति इस्लामी आक्रांताओं के कृत्यों के लिए वर्तमान भारतीय मुसलमानों को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। परंतु क्या आज के मुसलमानों को इस्लामी आक्रमणकारियों से स्वयं को जोड़कर इस पर गौरव करना चाहिए? यदि हिटलरवादियों-यहूदियों के आपसी संबंध मधुर नहीं हो सकते और गांधीजी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की बड़ाई से क्रोध उत्पन्न होता है, तो भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात करने वाले औरंगजेब जैसे क्रूर आक्रांताओं का गौरवगान कोई सभ्य समाज कैसे स्वीकार कर सकता है?

बदहाल पाकिस्तान : जफर एक्सप्रेस की खबर दहलाने वाली

ज्योति भास्कर

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित बोलन स्टेशन पर बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के अलगाववादियों द्वारा जफर एक्सप्रेस ट्रेन को अगवा करने और 180 से भी ज्यादा यात्रियों को बंधक बनाने की खबर दहलाने वाली तो है ही, पहले से ही खस्ताहाल पाकिस्तान की सुरक्षा और स्थिरता पर भी प्रश्नचिह्न खड़े करती है। यह घटना पाकिस्तान में अराजकता और बढ़ते जन असंतोष को भी दर्शाती है। बलूचिस्तान से गुजरने वाली जफर एक्सप्रेस पर यह कोई पहला हमला नहीं है। दरअसल, इस ट्रेन पर अक्सर सरकारी कर्मचारी, सैनिक और अधिकारी वगैरह चलते हैं, इसीलिए बीएलए की इस पर नजर रहती है।

उल्लेखनीय है कि बीएलए अफगानिस्तान के दक्षिणी हिस्से में सक्रिय एक बलूच राष्ट्रवादी चरमपंथी संगठन है, जिसका उद्देश्य बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर स्वतंत्र राष्ट्र बनाना है। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से भी समृद्ध प्रांत है और उसकी लड़ाई इस बात को लेकर है कि पाकिस्तान उसके संसाधनों का दोहन तो करता है, लेकिन बदले में स्थानीय लोगों को कोई फायदा नहीं मिलता।?पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ भी यह पिछले करीब सात दशकों से लड़ रहा है। चूंकि बीएलए की गतिविधियों को स्थानीय स्तर पर पूरा समर्थन मिला हुआ है, इसलिए पाकिस्तान ने बात करने के बजाय 2006 में ही बीएलए पर प्रतिबंध लगा दिया था।

गौरतलब है कि आईएमएफ के कर्ज के बोझ तले पाकिस्तान आर्थिक बदहाली से तो जूझ ही रहा है,?वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की 2025 की रिपोर्ट में भी उसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आतंक प्रभावित देश बताया गया था। आंकड़े यह भी बताते हैं कि 2024 में पाकिस्तान में आतंकी हमलों में 1,600 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जो पिछले एक दशक में सर्वाधिक मौतों वाला वर्ष भी है। विडंबना देखिए कि पाकिस्तान ने जिस आतंक को हमेशा प्रश्रय दिया, आज वही उसके भी गले की हड्डी बना हुआ है। आज के हालात देखते हुए तो गनीमत समझी जानी चाहिए कि पाकिस्तान में हाल ही में आयोजित आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी सुरक्षित ढंग से निपट गई।?

अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी इस स्थिति पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक ढंग से नहीं संभाल पाया, तो?यह पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की फितरत कुछ ऐसी है कि वह जब भी आंतरिक मुद्दों से जूझता है, तो ध्यान भटकाने के लिए भारत विरोधी सुर अलापने लगता है, ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वह पूरी सतर्कता के साथ पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए रखे।

नेता धार्मिक भावनाओं को राजनीतिक लाभ में बदलने से बचें

पूनम आई. कौशिश

कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि गुलमर्ग के एक सुरम्य रिजॉर्ट में स्कीवीयर की प्रदर्शनी का एक निजी कार्यक्रम राजनीतिक तूफान खड़ा कर देगा, किंतु ऐसा हुआ। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नैशनल कांफ्रैंस और पी.डी.पी. के विधायकों ने इसे रमजान के दौरान अश्लील और भड़काऊ कहकर इसकी निंदा की। हुर्रियत ने इसकी आलोचना कश्मीर के नैतिक मूल्यों को नष्ट करने का कार्यक्रम बताकर की और यहां तक कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसकी जांच के आदेश दिए तो भाजपा ने इसे यह कहकर खारिज किया कि पुरातनपंथी विचारों को भड़काया जा रहा है। सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों के संबंध में विविध विचारों को स्वीकार किया जाना चाहिए।

राजनीतिक दृष्टि से इस कार्यक्रम के बारे में यह हल्ला-गुल्ला मुस्लिम बहुल राज्य में बहुसंख्यकवाद द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन है और वे इस अश्लीलता को युवा मनों को विकृत करने के लिए एक आक्रामक औजार के रूप में देख रहे हैं और इस तरह राजनेता आम आदमी की भावनाओं का दोहन करने में व्यस्त हैं। यह उन्हीं हिन्दू कट्टरवादियों की तरह है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर काली माता को सिगरेट पीते हुए दिखाने पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए एक फिल्म निर्माता की या हिन्दू देवी को गलत ढंग से प्रस्तुत करने पर प्रसिद्ध चित्रकार हुसैन की गिरफ्तारी की मांग की थी। इसमें

दोषी कौन है? हमारे नेता गत वर्षों में समाज में जहर घोलने के लिए अनुचित भाषा का इस्तेमाल करने में सिद्धहस्त हो गए हैं। राजनीति ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण और कट्टरवाद की संकीर्ण गलियों तक सीमित हो गई है और इसके चलते हिन्दू और मुसलमानों को एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर सांप्रदायिक मतभेद बढ़ाए जा रहे हैं। कोई परवाह नहीं करता है कि यह सांप्रदायिकता के बीज बोकर विनाश की ओर ले जा रहा है और राष्ट्र इसमें उलझता जा रहा है। विद्वेषपूर्ण आरोपों से क्या प्राप्त होता है? कुछ भी नहीं। विवाद और मतभेद पैदा करने से कुछ प्राप्त नहीं होता।

राजनेताओं, कार्यकर्त्ताओं और बुद्धिजीवियों का दावा है कि भारत विसंगतियों का मंच बन रहा है, जिससे यह स्वघोषित उग्र राष्ट्रवाद के शिकंजे में आ गया है, जहां पर आलोचक और बुद्धिजीवी आसान निशाना बन जाते हैं और बहस, वाद-विवाद तथा विवेकपूर्ण निर्णयों का स्थान अविवेकपूर्ण प्रतिक्रिया लेने लगी है।

प्रत्येक ट्वीट, हास-परिहास को गलत समझा जाता है और इससे सार्वजनिक बहस दंतविहीन बन जाती है तथा यह हमारे गणतंत्र के मूल्यों तथा आधारभूत सिद्धान्तों के विपरीत है। पुरातनपंथी वाद-विवाद बढ़ते जा रहे हैं और यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा व्यक्तिगत पसंद बनाम असहिष्णुता के संबंध में एक खतरनाक राजनीतिक प्रवृत्ति को जन्म दे रहा है, जो इसी तरह निर्बाध बढ़ती रही तो समाज खतरनाक रूप से कट्टरपंथी और खंडित हो जाएगा। निश्चित रूप से प्रत्येक समुदाय में ऐसे लोग हैं जो हर समय समस्या पैदा करना चाहते हैं, किंतु सभी धर्मों में इस तरह के अविवेकपूर्ण लोग हमारे जीवन को कठिन बना रहे हैं और वे हमें हमारे ज्वलंत मुद्दों महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी आदि पर विचार करने का अवसर नहीं दे रहे।

सरकार को संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और विविध मतों और धर्मावलंबियों के लिए समानता सुनिश्चित करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विविधता का पूर्ण सम्मान किया जाए। साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि भारत में प्रत्येक नागरिक को कुछ बुनियादी अधिकार प्राप्त हैं और जब विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात आती है तो इन्हें हमारे संवैधानिक व्यवस्था में सर्वोच्च महत्व दिया गया है।

यह सच है कि अनुच्छेद 19 में वस्त्र पहनने की स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लेख नहीं है किंतु अभिव्यक्ति में वस्त्र पहनने का अधिकार भी समाहित है क्योंकि वस्त्र भी एक प्रकार की अभिव्यक्ति है। तथापि यह अधिकार परम नहीं है और यह उचित प्रतिबंधों के अध्याधीन है। कोई व्यक्ति क्या पहने, जब तक यह लोक लाज के विरुद्ध न हो। स्पष्ट है कि प्रतिस्पर्धी लोकतंत्र के वातावरण में धर्म के आधार पर राजनीति से मतदाताओं के ध्रुवीकरण के आसार बढ़ जाते हैं। इसलिए समय आ गया है कि हम सांप्रदायिकता के बीज बोने से बचें। जिस धार्मिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है वह खतरनाक है। समय आ गया है कि हमारे राजनेता अपने कार्यों के प्रभावों को समझें क्योंकि इससे लोग पंथ और धर्म के आधार पर विभाजित होंगे और एक तरह से एक दैत्य पैदा होगा। धर्म को राजनीति से अलग करना होगा तथा विभाजनकारी राजनीति पर प्रतिबंध लगाने के बारे में विचार करना होगा। यह बात समझनी होगी कि विभिन्न समुदायों को एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर वे केवल अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं। संवैधानिक प्राधिकारियों से विवेक और संयम की अपेक्षा की जाती है। उद्देश्य राजनीतिक चर्चा का स्तर उठाने का होना चाहिए न कि उसे गिराने का। जब हमारे राजनेता लागत लाभ का विश्लेषण करें तो उन्हें इस सरल से प्रश्न का उत्तर देना होगा कि क्या उनकी सांप्रदायिक वोट बैंक की राजनीति इस योग्य है कि देश की जनता उसकी कीमत चुकाए? इसके लिए कौन दोषी है? कुल मिलाकर, हमारे नेताओं को समझना होगा कि राष्ट्र पहले दिलों और मनों का मिलन है और उसके बाद यह एक राजनीतिक इकाई है। हमें इसे राजनीतिक प्रचार के साधन के रूप में केवल एक फैशन शो नहीं बनाना चाहिए। हमारे नेताओं को लागत-लाभ का विश्लेषण करना चाहिए और धार्मिक भावनाओं को राजनीतिक लाभ में बदलने से बचना चाहिए।

हिंदी को राजभाषा का दर्जा : वरदान या श्राप

योगेन्द्र यादव

हिंदी के राजभाषा बनने से हम हिंदी भाषियों को क्या मिला? एक अदद हिंदी दिवस, जिसकी उबाऊ सरकारी रस्म हमें याद दिलाती है कि बाकी 364 दिन अंग्रेजी दिवस हैं। राजभाषा अधिकारियों की चंद नौकरियां, जिसके सहारे हीनताबोध को आक्रामकता में बदला जा सके। राजभाषा विभाग की बनाई एक कृत्रिम भाषा, जिसे न कोई बोलता, न समझता है। एक झूठी ऐंठ। हिंदी पट्टी की दर्जनों भाषाओं से सौतेला रिश्ता। और गैर हिंदी भाषियों से बिना बात का झगड़ा। इस राजभाषा के झंझट से पिंड क्यों न छुड़ा लिया जाए?

यह सवाल मेरे मन में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बयान को पढ़कर आया। तमिलनाडु सरकार क्षुब्ध है कि केंद्र ने समग्र शिक्षा योजना के तहत तमिलनाडु की 2000 करोड़ से अधिक राशि इस कारण रोक ली कि वह नई शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा फार्मूले को लागू नहीं कर रही। मुख्यमंत्री का गुस्सा स्वाभाविक था, चूंकि त्रिभाषा फार्मूले से तमिलनाडु की असहमति आज से नहीं, बल्कि 50 साल से जगजाहिर है। इस आधार पर केंद्र के अनुदान को रोकना राजनीतिक शरारत के सिवा कुछ नहीं हो सकता।

वैसे नई शिक्षा नीति के संशोधित त्रिभाषा फार्मूले में हिंदी की कोई अनिवार्यता नहीं है, लेकिन इसे राजनीतिक संदर्भ में डी.एम.के. ने त्रिभाषा सूत्र को पिछले दरवाजे से हिंदी लादने के षड्यंत्र के रूप में देखा और इसके खिलाफ जंग छेड़ दी। मुझे इस बात का दुख हुआ कि केंद्र सरकार की बेजा हरकत के चलते त्रिभाषा सूत्र खामखा बदनाम हो रहा है। दुख और भी गहरा था चूंकि त्रिभाषा सूत्र का सत्यानाश तमिलनाडु ने नहीं, बल्कि हिंदी भाषी राज्यों ने किया था। संस्कृत के बहाने किसी भी गैर हिंदी भाषा को सीखने से छुट्टी

लेकर हिंदी भाषी राज्यों ने त्रिभाषा सूत्र की भावना से खिलवाड़ किया। अगर त्रिभाषा सूत्र का मतलब यह है कि गैर हिंदी भाषी तो हिंदी सीखेंगे लेकिन हिंदी भाषी और किसी की भाषा नहीं सीखेंगे तो इससे ड्क्षहदी के प्रति चिढ़ पैदा होगा स्वाभाविक है।

अपने पलटवार में स्टालिन ने सिर्फ हिंदी लादने की नीति पर ही नहीं, हिंदी भाषा पर भी हमला बोल दिया। अन्य सभी राज्यों के नागरिकों को हिंदी के विस्तारवाद से आगाह करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा ने उत्तर भारत की दर्जनों भाषाओं को निगल लिया है। अपने बयान में भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रज, बुंदेली, गढ़वाली, कुमाउंनी, मगघी, मारवाड़ी, मालवी, छत्तीसगढ़ी, संथाली, अंगिका, हो, खरिया, खोरता, कुर्मली, कुरुक, मुंडारी को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी ने इन सभी भाषाओं को लगभग खत्म कर दिया है।

किसी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा एक अन्य भाषा पर ऐसी टिप्पणी मुझे बेजा लगी। यूं भी अनेक भाषाओं को समेट कर एक 'मानक भाषा' बनाने का दोष सिर्फ हिंदी को देना गलत होगा। यह प्रक्रिया कमोबेश प्रत्येक आधुनिक भारतीय 'मानक भाषा' के निर्माण में दोहराई गई है। मैंने यह कहते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से अपनी 'दोस्ताना असहमति' दर्ज की। बस इतने में उनके सभी समर्थक सोशल मीडिया पर टूट पड़े। मुझे हिंदी वर्चस्ववादी और न जाने क्या-क्या गालियां दी गईं। मुझे दुख तो हुआ, मगर हैरानी नहीं। पिछले कुछ वर्षों में हमने सार्वजनिक संवाद में इस निम्न स्तर की गाली-गलौच और असहिष्णुता की संस्कृति बनाई है कि कुछ बेहतर की उम्मीद करना बेकार होता। लेकिन इस संवाद से मेरे मन में यह सवाल उठा कि अगर हिंदी को राजभाषा का रस्मी दर्जा न होता तो क्या अन्य भारतीय भाषा-भाषियों में हिंदी के प्रति ऐसी शंका और चिढ़ होती? क्या मिला हिंदी को राजभाषा बनने से?

एक बात तो तय है। राजभाषा बनने से हिंदी भाषा का कोई भला नहीं हुआ। 'असर' सर्वे की रिपोर्ट हर साल हमें याद दिलाती है कि हिंदी जनपद के राज्यों में स्कूली बच्चों का हिंदी ज्ञान दयनीय है। 5वीं कक्षा के आधे से अधिक बच्चे ड्क्षहदी की दूसरी कक्षा की किताब का साधारण सा पैरा भी नहीं पढ़ सकते। मेरा अपना अनुभव है कि इन राज्यों में हिंदी माध्यम से बी.ए. के डिग्रीधारी विद्यार्थी हिंदी व्याकरण तो छोड़िए, वर्तनी भी नहीं जानते। अधिकांश लोग 'आशीर्वाद' को 'आशिर्वाद' लिखते हैं। कोई 60 करोड़ लोगों की इस भाषा में एक भी अंतरराष्ट्रीय स्तर का अखबार नहीं है। साहित्य की कुछ अच्छी पत्रिकाएं हैं, लेकिन देश और दुनिया की विवेचना करने वाली 'दिनमान' जैसी एक भी पत्रिका जीवित नहीं है। आज भी ज्ञान और विज्ञान की मूलभूत पाठ्य पुस्तकें हिंदी में नहीं हैं। हिंदी भाषी खुद हिंदी बोलने में झेंपते हैं, टूटी-फूटी अंग्रेजी बोलने में शान समझते हैं। हिंदी भाषी संभ्रांत परिवार अपनी बैठक में हिंदी की पत्र-पत्रिका को रखने में हेठी समझते हैं। यह है उस महारानी की हकीकत, जिसके वर्चस्व से बाकी सब आक्रांत हैं!

हिंदी जगत में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, विस्तार भी हो रहा है। हिंदी के लेखक दुनिया का उत्कृष्ट साहित्य रच रहे हैं। हिंदी सिनेमा नवीन प्रयोग कर रहा है। टी.वी. समाचार के जगत में हिंदी चैनलों का बोलबाला है। क्रिकेट कमैंटरी के लिए दर्शक अब हिंदी पर निर्भर नहीं हैं, फिर भी हिंदी सबसे आगे है। विज्ञापनों की दुनिया में भी हिंदी बढ़ी है, चाहे रोमन लिपि में ही। लेकिन यह सब समाज और बाजार की देन हैं, सरकारी राजभाषा से इनका कोई लेना-देना नहीं है। दरअसल सरकारी राजभाषा की संस्कृतनिष्ठ शब्दावली हिंदी के इस स्वाभाविक विकास के रास्ते में अड़चन है।

राजभाषा से हिंदी को मिला है अन्य भारतीय भाषाओं से अलगाव। अपनी समकक्ष और अपने से पुरानी और समृद्ध भाषाओं से सास जैसा व्यवहार करने की फूहड़ प्रवृत्ति। जिन भाषाओं ने हिंदी का पोषण किया, उन्हें बोलियों का दर्जा देकर उनसे सौतेला रिश्ता बनाया। अंग्रेजी के सामने अलग-अलग खड़े होकर सांस्कृतिक स्वराज की लड़ाई हारने की मजबूरी। यह वरदान नहीं श्राप है। आज की हालत से तो कहीं बेहतर होगा कि हम हिंदी भाषा-भाषी जन खुद राजभाषा रूपी इस सिंहासन को हटाने की मांग करें। मतलब यह नहीं कि हिंदी की बजाय अंग्रेजी को राजभाषा बना दें, बल्कि 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा देने की मांग करें। गैर हिंदी इलाकों में हिंदी के प्रचार-प्रसार को छोड़कर पहले हम हिंदी क्षेत्र में हिंदी को संपन्न बनाएं। हिंदी भाषा को सरकार की बजाय समाज के हाथ में लौटा दें। हिंदी दिवस को मातृभाषा दिवस बनाने की मांग करें, ताकि अंग्रेजी के वर्चस्व का मुकाबला करने के लिए हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं के साथ खड़ी होकर सांस्कृतिक स्वराज की लड़ाई लड़ सके।

धन बल और बाहुबल सियासत पर हावी

राजेश बादल

भारतीय लोकतंत्र का एक विकृत संस्करण इन दिनों हम देख रहे हैं। वैसे तो कुछ दशकों से इस जम्हूरियत में सामंती बीज पनपते दिखाई दे रहे थे। वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आड़ में अंकुरित होते गए। सामूहिक नेतृत्व के स्थान पर जैसे-जैसे धन बल और बाहुबल सियासत पर हावी होता गया, उसमें समूचा तंत्र व्यक्ति के इर्दगिर्द सिमटता गया। यानी जिस रौबदार नेता के पास पैसा और हथियारों से लैस सेना थी, वह हावी होता गया। लोकतंत्र की मूल भावना इस तरह धीरे-धीरे दम तोड़ती गई। एक व्यक्ति के रौब में आकर पार्टियां पनपती रहीं। इसके लिए किसी एक दल को दोष नहीं दिया जा सकता। कमोबेश प्रत्येक राजनीतिक पार्टी में इसका दुष्प्रभाव नजर आ रहा है। अफसोस यह है कि राजनीति में उतरने वाली नई नस्लें इस विकृत रूप को ही असल लोकतंत्र समझ बैठी हैं। अनेक पार्टियों का आंतरिक ढांचा इस तथ्य का सबूत है कि उनका मुखिया एक राजा की तरह ही व्यवहार करता है। उनके उत्तराधिकारी खुद को राजकुमार या युवराज समझते हैं। दरअसल भारतीय लोकतंत्र की यह ऐसी सड़ांध या महामारी है, जिसका असर आने वाले दिनों में उजागर होगा। राष्ट्रीय दल बहुजन समाज पार्टी के भीतर का घटनाक्रम इसका ताजा उदाहरण है। राष्ट्र के बौद्धिक मंच पर इसकी चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन कहीं भी इस पर बहस नहीं हुई। बहुजन समाज पार्टी में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी की मुखिया मायावती ने चंद रोज पहले जिस तरह भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाला, वह किसी भी कीमत पर अच्छी राजनीति का लक्षण नहीं है। भले ही वह पार्टी का अंदरूनी मामला था, मगर निकालने से पहले न कोई कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई और न आकाश आनंद से स्पष्टीकरण मांगा गया। वह लोकतांत्रिक ढंग नहीं था। पर इससे ज्यादा खतरनाक मायावती का अंदाज था, जिस पर सियासी जमात के किसी प्रतिनिधि का ध्यान नहीं गया। उन्होंने दो बरस पहले आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन अचानक उनको निकाल दिया गया। इससे पहले उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ तथा पत्नी प्रज्ञा को भी मायावती ने निकाल दिया था। आठ बरस पहले आकाश लंदन से पढ़ाई पूरी करके आए थे और मायावती के अनुरोध पर ही पार्टी से जुड़े थे। वे पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक भी थे। लेकिन मायावती के कोप का शिकार हो गए और समन्वयक पद से भी बर्खास्त कर दिए गए। इसके बाद उन्हें पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले फिर प्रमुख दायित्व सौंपे गए। साल भर पूरा होते-होते आकाश पर फिर गाज गिरी और उन्हें दरवाजा दिखा दिया गया। मायावती से यह सवाल पूछा जा सकता है कि आखिर उनकी पार्टी में नियुक्तियां क्यों होती हैं? जनतांत्रिक तरीके से निर्वाचन क्यों नहीं कराए जाते? सवाल यह नहीं है कि उन्हें बार-बार जिम्मेदारियां सौंपी गईं और हटाया गया। असल सवाल यह है कि मध्ययुग में जिस तरह राजा या सुल्तान बर्ताव करते थे, मायावती का रवैया कुछ इसी प्रकार का है। एक राजा अपने किसी एक प्रिय राजकुमार को उत्तराधिकारी चुनता था। वह राजा बन जाता था। लेकिन किन्ही कारणों से राजा उस राजकुमार से खफा हो जाए तो उसको भी हटा देता था। इसी तरह कुनबे का राज चलता था। भारत की आजादी के बाद हमने जिस संवैधानिक लोकतंत्र को अपनाया, उसमें ऐसी राजसी मानसिकता के लिए कोई स्थान नहीं था। मध्ययुग की मानसिकता के साथ चल रहीं मायावती लंदन में पढ़े-लिखे एक नौजवान से क्या अपेक्षा कर रही थीं? वह भी कबीलाई संस्कृति अपना ले? दो पीढ़ियों के बीच यह तनातनी तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी से लेकर दक्षिण भारत के डीएमके और अन्य मंझोले दलों में वर्षों से चल रही है। ममता बनर्जी का भतीजे से मतभेद, शरद पवार का भतीजे से मतभेद, अखिलेश यादव का चाचा से मतभेद, झारखंड मुक्ति मोर्चा में पारिवारिक कलह, बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा - भतीजे में टकराव और आरजेडी में दो भाइयों के बीच मतभेद कुछ उदाहरण हैं। अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में इस तरह के उदाहरण कम हैं। हां उनके व्यवहार और शब्दों में सामंती लहजा अवश्य नजर आने लगा है। मध्य प्रदेश में एक पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा वर्तमान में राज्य सरकार में मंत्री ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दरम्यान अजीबोगरीब बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। कहीं जाते हैं तो मांगपत्र लिए भिखारियों की भीड़ चली आती है।

कला, संस्कृति और शिक्षा का संगम आयरलैंड

योरप के पश्चिमी छोर पर स्थित नन्हा-सा देश रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जहां अपने सुदीर्घ इतिहास और कला-संस्कृति के लिए जाना जाता है, वहीं शिक्षा के लिहाज से भी यह विदेशी विद्यार्थियों को आकर्षित कर रहा है। आयरलैंड की कला और संस्कृति को योरप क्या, संपूर्ण विश्व में आदर के साथ देखा जाता है। बड़े-बड़े साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में यहां के जीवन, प्राकृतिक सौंदर्य, संस्कृति एवं सभ्यता का बखूबी बखान किया है। आयरिश संगीत एवं नृत्य को भला कौन नहीं जानता! यहां के प्राचीन किले वास्तुकला का बखान करते हैं।

आयरलैंड को उसकी उन्नात शिक्षा प्रणाली के लिए भी जाना जाता है। दीर्घकाल से यहां विदेशी विद्यार्थियों की उपस्थिति रही है। यहां सरकारी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के अलावा बड़ी संख्या में गैर-सरकारी कॉलेज एवं टेक्निकल इंस्टीट्यूट मौजूद हैं। डबलिन का ट्रिनिटी कॉलेज आयरलैंड का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1592 में की गई थी।

शोध में शीर्ष पर

विश्व के सभी देशों में आज शोध कार्यों को वरीयता दी जा रही है। आयरलैंड भी इससे अछूता नहीं है। शोध कार्यों को यहां प्रोत्साहित किया जाता है। शिक्षण संस्थानों का प्रयास रहता है कि इस काम में किसी भी तरह की अड़चन न आए। यहां से शोध कार्य करके निकले विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में शीर्ष मुकाम हासिल करने में सफल हुए हैं। आयरलैंड के कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक माहौल स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करके अपने आप को शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा में बनाए रखना होता है।

विषयों की बहुलता

आयरलैंड में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों के सामने विषय का चयन कोई आसान काम नहीं है। विषयों की अधिकता और सभी में उत्कृष्ट शिक्षा उन्हें अनेक विकल्प उपलब्ध कराती है। मसलन, आयरलैंड और साहित्य के बीच गहरा नाता है। यहां का लगभग प्रत्येक नागरिक कहीं-न-कहीं साहित्य के प्रति गहरी आस्था रखता है। यहां के कई साहित्यकारों ने विश्व साहित्य पर अपनी छाप छोड़ी है। विदेशी विद्यार्थी हों या स्थानीय, दोनों ही लिटरेचर कोर्सेस में खासी दिलचस्पी दिखाते हैं। आयरलैंड ने एक ओर जहां आधुनिक तकनीक को अपनाया है, वहीं अपनी प्राचीन परंपराओं को भी सहेजकर रखा है। शिक्षण संस्थानों में गौरवशाली प्राचीन संस्कृति से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, वहीं हर आधुनिक तकनीक विद्यार्थियों को मुहैया कराई जाती है। यहां के समस्त शिक्षण संस्थानों में कम्प्यूटर एजुकेशन पर विशेष जोर दिया जाता है। साहित्य एवं टेक्नोलॉजी तो स्थानीय एवं विदेशी विद्यार्थियों की वरीयता सूची में हैं ही, लेकिन अब कम्यूनिकेशन और इतिहास विषय भी इस सूची में शामिल हो गए हैं। इन विषयों में विद्यार्थियों को आधुनिकतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

अन्य सुविधाएं

अगर आप आयरलैंड में पढ़ाई के साथ-साथ काम भी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको उस संस्थान की अनुमति लेनी होगी, जहां आपने प्रवेश लिया है। निर्धारित नियमों के अंतर्गत सोच-विचार करके आपको सप्ताह में कुछ घंटे तक जॉब करने की अनुमति मिल सकती है।

दवा मार्केटिंग के मास्टर

फार्मास्युटिकल उद्योग तेजी से बढ़ने वाले उद्योगों में से एक है। शानदार ग्रोथ की वजह से इसमें नौकरियां भी तेजी से बढ़ी हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं और सेल्स तथा कस्टमर को मैनेज करने का हुनर रखते हैं, तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में करियर की बेहतरीन शुरूआत कर सकते हैं। भारत का फार्मा सेक्टर 13-14 फीसदी सालाना की दर से ग्रो कर रहा है। मेडिकल फील्ड में हो रही गतिविधियों के कारण मेडिसिन मार्केट भी कमर्शियल रूप से काफी आगे बढ़ रहा है। एफडीआई के बाद से इसमें और विस्तार होने की उम्मीद की जा रही है। कई विदेशी कंपनियां अपने उत्पादों का पेटेंट कराकर भारत में कारोबार करने आ रही हैं। इससे घरेलू फार्मा इंडस्ट्री और तेजी से विकसित हो रही है। इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस फील्ड में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए जॉब्स की कमी नहीं होगी।

मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स फार्मास्युटिकल कंपनीज और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के बीच की कड़ी होते हैं। वे उत्पादों को एक रणनीति के साथ बाजार में प्रमोट करते हैं। वन-टु-वन के अलावा वे ग्रुप इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर दवाइयों के प्रति जागरूक करते हैं। फार्मास्युटिकल कंपनीज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को नियुक्त करती हैं, ताकि वे कस्टमर्स और डॉक्टर्स को अपने प्रोडक्ट की उपयोगिता के प्रति संतुष्ट कर सकें। इस तरह मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दवाइयों की मार्केटिंग में एक अहम भूमिका निभाते हैं। अलग-अलग दवा कंपनियां अपने यहां नियुक्ति के बाद कैंडिडेट्स को स्पेशल स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देती हैं। उन्हें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, सेल्समैनशिप की ट्रेनिंग के अलावा डॉक्टर्स की प्रोफाइल, उत्पादों की जानकारी और फील्ड ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके तहत सैलिंग टेक्नीक्स बताई जाती हैं। फील्ड ट्रेनिंग के दौरान फ्रेश ग्रेजुएट्स को किसी सीनियर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के अधीन काम करना होता है।

जरूरी स्किल्स

मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए आपके पास मेडिकल फील्ड, मैनेजमेंट और मेडिसिन की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। आपको मानव शरीर और दवा में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक तत्वों की भी जानकारी रखनी होगी। ऐसे में आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ-साथ अंग्रेजी-हिंदी की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इस फील्ड में काम के कोई तय घंटे नहीं होते हैं, इसलिए आपको इसके लिए पहले से तैयार रहना होगा। खुद को फिजिकली भी फिट रखना होगा।

एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन

फार्मा बिजनेस मैनेजमेंट में बीबीए या एमबीए, फार्मास्युटिकल एंड हेल्थकेयर मार्केटिंग में पीजी डिप्लोमा, फार्मा मार्केटिंग में डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा, सेलिंग और मार्केटिंग की स्किल रखने वाले साइंस ग्रेजुएट्स भी एंट्री ले सकते हैं। आज कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में इससे संबंधित कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। कुछ संस्थानों में फार्मा बिजनेस मार्केटिंग से संबंधित कोर्स भी शुरू हो चुके हैं। डिप्लोमा कोर्स करने के लिए आपको साइंस के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में प्रवेश के लिए स्टूडेंट्स के पास बीएससी, बीफार्मा की डिग्री होनी चाहिए। 12वीं (मैथ्स और बायोलॉजी) के बाद बीबीए (फार्मा बिजनेस) में दाखिला लिया जा सकता है।

सैलरी पैकेज

सामान्य तौर पर शुरूआती वेतन 10 से 20 हजार रुपए तक होता है लेकिन अनुभव के आधार पर आमदनी में इजाफा होता रहता है। कुछ अनुभव हासिल करने के बाद 30 से 40 हजार रुपए प्रतिमाह आसानी से हासिल किए जा सकते हैं। पांच या सात साल के अनुभव के बाद वेतन लाखों में हो सकता है। इसके अलावा, आपके परफॉर्मेंस के आधार पर समय-समय पर इंसेंटिव सहित कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। सेल्स टारगेट अचीव करने वालों को कई बार ब्रांड मैनेजमेंट जैसी जिम्मेदारी तक सौंप दी जाती है। इससे आपकी आमदनी बढ़ने के साथ-साथ मार्केट में एक अलग पहचान बनती है।

तरक्की की संभावनाएं

सेल्स परफॉर्मेंस और कस्टमर्स को मैनेज करने का हुनर रखने वाले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फार्मास्युटिकल मार्केटिंग में शानदार करियर बना सकते हैं। जो लोग कंपनी के टारगेट को समय-समय पर अचीव करते चलते हैं, उन्हें प्रमोशन मिलने में भी देर नहीं लगती है। आप एरिया मैनेजर, रीजनल या जोनल मैनेजर, डिवीजनल सेल्स मैनेजर, डिवीजनल कंट्रोलर, डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर के अलावा मार्केटिंग मैनेजर के रूप में प्रमोशन पा सकते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के अलावा, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव, बिजनेस एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करने का पूरा अवसर है। एमबीए या फार्मेसी की डिग्री रखने वाले एरिया मैनेजर, सर्कल मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर, क्वॉलिटी कंट्रोल मैनेजर, ब्रांड मैनेजर या मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में दवा कंपनियों के साथ जुड़ सकते हैं। इन कंपनियों में एक-दो साल का अनुभव रखने वाले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को इंटरव्यू के आधार पर नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा, समय-समय पर अखबारों में और वेब साइट्स पर भी विज्ञापन निकलते रहते हैं।

यूं बढ़ रही है स्किल्ड ब्रांड मैनेजर्स की मांग

आज भारतीय उपभोक्ताओं के पास हर उत्पाद के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं, क्योंकि हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ग्राहक को आकर्षित करने की कोशिश करती है। इस पूरी प्रक्रिया में ब्रांडिंग की बड़ी भूमिका होती है।

उपभोक्ता के मन में एक प्रोडक्ट की स्थायी जगह बनाने में ब्रांडिंग का बड़ा हाथ होता है। हर बड़ी कंपनी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बाजार में प्रमोट करने के लिए ब्रांड मैनेजर्स को हायर करती है। ब्रांडिंग प्रक्रिया में नए उत्पाद के लॉन्च होने से लेकर उसे उपभोक्ता की जिंदगी का अहम हिस्सा बनाने तक की रणनीति शामिल होती है। हर कंपनी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की ब्रांडिंग के लिए ऐसे लोगों को हायर करना चाहती है, जिनके पास प्रमोशन के विभिन्न आइडियाज हों। अगर आप भी इस तरह के करियर ऑप्शन की तलाश में हैं, तो ब्रांड मैनेजमेंट आपके लिए आदर्श करियर बन सकता है।

कैसे करें शुरूआत?

ब्रांड मैनेजमेंट में करियर बनाने के लिए आप ग्रेजुएशन के बाद ब्रांड मैनेजमेंट से एमबीए करके स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा एमबीए-मार्केटिंग से स्पेशलाइजेशन करके इस करियर को शुरू किया जा सकता है।

करियर की संभावनाएं

ब्रांड मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद फ्रेशर्स को एंट्री लेवल पर असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर की जॉब मिल सकती है। अपने अच्छे आइडियाज, परफॉर्मेंस और इनोवेशन से उम्मीदवार मिड लेवल तक पहुंच सकते हैं यानी ब्रांड मैनेजर बन सकते हैं।

किस एरिया में जॉब?

प्रतिभाशाली और स्किल्ड ब्रांड मैनेजर्स की मांग फार्मास्युटिकल, मोबाइल, इंश्योरेंस, हेल्थकेयर कंपनियों, मीडिया हाउसेस, ऑटोमोबाइल कंपनीज वगैरह में काफी है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए हर कंपनी अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग आकर्षक तरीके से करनी चाहती है।

कितना पैकेज?

इस इंडस्ट्री में फ्रेशर्स का स्टार्टिंग सैलेरी पैकेज तीन से साढ़े तीन लाख प्रति वर्ष हो सकता है। सैलेरी पैकेज इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कौन-से संस्थान में और किस शहर में काम कर रहे हैं।

ये गुण जरूरी

ब्रांड मैनेजर बनने के लिए एक व्यक्ति को न मोटिवेटेड और बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहना जरूरी होता है।

- अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए।
- सुपरविजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्लानिंग स्किल्स में भी आगे होने चाहिए।
- उम्मीदवार किस तरह के आइडियाज के साथ प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कितने क्रिएटिव तरीके से करते हैं और उसका कैसा रिस्पांस मिलता है, यह भी बहुत मायने रखता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

केटीआर का राहुल गांधी पर वार

हैदराबाद। वरिष्ठ पत्रकार रेवती और उनकी सहकर्मी तन्वी यादव को बुधवार को हैदराबाद में उनके आवास से पुलिस ने कथित तौर पर गिरफ्तार कर लिया। दोनों को सुबह करीब 5 बजे हिरासत में लिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस शासन में अपनी कठिनाइयों के बारे में बात करने वाले एक किसान का वीडियो पोस्ट किया था। तड़के महिला पत्रकारों की गिरफ्तारी से आक्रोश फैल गया, और बीआरएस नेताओं ने रेवंत रेड्डी सरकार की सत्तावादी रणनीति की निंदा की। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक केटी रामा राव (केटीआर) ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर निशाना साधा। केटीआर ने एक्स पर लिखा, क्या यही आपकी मोहब्बत की दुकान है राहुल गांधी जी? सुबह-सुबह दो महिला पत्रकारों को गिरफ्तार करना!! उनका अपराध क्या है? अक्षम और भ्रष्ट कांग्रेस सरकार के खिलाफ़ जनता की राय को आवाज़ देना।

दिल्ली पुलिस ने 12 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार

नईदिल्ली। दिल्ली पुलिस ने साउथ ईस्ट और साउथ दिल्ली से एक ऑपरेशन के दौरान 12 से ज्यादा बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है। ये बांग्लादेशी अवैध तरीके से भारत में घुसे थे। इनके पास से कई दस्तावेज़ बरामद हुए हैं। ऑपरेशन अभी भी जारी है। पुलिस ने बताया कि कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इससे पहले राजधानी में बांग्लादेशी नागरिकों सहित प्रवासियों के अनधिकृत प्रवास पर बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए, दिल्ली पुलिस ने वैध भारतीय दस्तावेजों के बिना रहने वाले व्यक्तियों की पहचान करने, उन्हें हिरासत में लेने और उन्हें वापस भेजने के प्रयास तेज कर दिए हैं। पुलिस ने बताया कि अभियान के तहत बांग्लादेश से आठ अवैध प्रवासियों का पता लगाया गया और उन्हें विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) के माध्यम से उनके देश वापस भेज दिया गया। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने पश्चिमी दिल्ली में वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से रह रहे दो बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा था।

भाजपा का 2500 रुपये का वादा साबित हुआ जुमला

नईदिल्ली। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि वे दिल्ली की महिलाओं से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहे हैं, जिसमें 2,500 रुपये की सहायता और मुफ्त एलपीजी सिलेंडर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली की जनता से कई वादे किए थे। 2500 रुपये का वादा जुमला साबित हुआ। दिल्ली की महिलाओं को होली के दौरान मुफ्त सिलेंडर मिलने थे। आतिशी ने आगे कहा कि होली में अब सिर्फ 1 दिन बचे हैं और दिल्ली की महिलाएं मुफ्त सिलेंडर का इंतजार कर रही हैं। दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में महिलाएं खाली सिलेंडर लेकर भाजपा और उनके झूठे वादों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। भाजपा ने महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता देने का वादा किया था।

केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर

नईदिल्ली। दिल्लीवासी जल्द ही नाव की सवारी का आनंद ले सकेंगे। दिल्ली सरकार और केंद्र ने सोनिया विहार और जगतपुर के बीच यमुना के 4 किलोमीटर लंबे हिस्से में जल पर्यटन विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। असिता पार्क में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि आने वाले दिनों में इस सुविधा का विस्तार किया जाएगा ताकि दिल्ली की सड़कों पर भीड़भाड़ कम हो और निवासियों को बेहतर यात्रा विकल्प मिल सकें। उन्होंने आगे कहा कि यह पहल नदी, सड़क और मेट्रो परिवहन प्रणालियों को एकीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, और यमुना कॉरिडोर के आगे के विकास के लिए एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल की भी खोज की जाएगी। उन्होंने यमुना की सफाई में हुई पिछली देरी को स्वीकार करते हुए कहा कि पहले इसे नाले की तरह माना जाता था।

जुमे की नमाज के लिए होली पर लगे दो घंटे का ब्रेक

नईदिल्ली। बिहार के दरभंगा की मेयर ने 14 मार्च को होली के जश्न के दौरान दो घंटे का ब्रेक देने का सुझाव देकर विवाद खड़ा कर दिया है, जो रमजान के पवित्र महीने में शुक्रवार की नमाज के साथ मेल खाता है। एक बयान में, मेयर अंजुम आरा ने प्रस्ताव दिया कि होली के उत्सव को दोपहर 12.30 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच अस्थायी रूप से रोक दिया जाना चाहिए क्योंकि जुम्मा (शुक्रवार की नमाज) का समय नहीं बदला जा सकता है। महापौर ने यह भी आग्रह किया कि होली मनाने वालों को जुमे के दौरान दो घंटे तक मस्जिदों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। अंजुम आरा ने आगे कहा, इससे पहले भी कई बार होली और रमजान का त्यौहार जिले में शांतिपूर्वक मनाया गया है। यह बयान जिला प्रशासन द्वारा इस सप्ताह की शुरुआत में शांति समिति की बैठक के बाद जारी किया गया। होली के साथ ही रमजान के महीने में जुमे की नमाज भी पड़ रही है, जिसे मुसलमान मनाते हैं, इसलिए, ज्यादातर शहरों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ के लिए पेश किया नया दृष्टिकोण

भारत और मॉरीशस के बीच अहम समझौते

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और मॉरीशस का संबंध सिर्फ हिंद महासागर ही नहीं, बल्कि हमारी साझी सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों से भी जुड़ा है। हम आर्थिक और सामाजिक प्रकृति की राह पर एक दूसरे के साथी हैं। प्राकृतिक आपदा हो या कोविड विपदा, हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम ने बुधवार को प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इसके बाद दोनों की मौजूदगी में भारत और मॉरीशस के बीच अहम समझौते भी किए गए। दोनों देशों ने आज 8 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान दोनों नेताओं ने संयुक्त बयान भी जारी किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि मॉरीशस हमारा एक अहम साझेदार है। सभी के लिए सुरक्षा और विकास- 'सागर' की परिकल्पना की नींव 10 साल पहले मॉरीशस में रखी गई थी। 'ग्लोबल साउथ' के लिए हमारा दृष्टिकोण 'महासागर' यानी सभी क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति होगा। हमारा दृष्टिकोण विकास के लिए व्यापार, उन्नति के वास्ते दक्षता विकास और साझा भविष्य के लिए आपसी सुरक्षा पर केंद्रित है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं मॉरीशस के सभी नागरिकों को राष्ट्रीय दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस पर फिर से आने का अवसर मिला है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम और मॉरीशस सरकार का आभार व्यक्त करता हूं।

उन्होंने कहा, भारत और मॉरीशस का संबंध सिर्फ हिंद महासागर ही नहीं, बल्कि हमारी साझी सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों से भी जुड़ा है। हम आर्थिक और सामाजिक प्रकृति की राह पर एक दूसरे के साथी हैं। प्राकृतिक आपदा हो या कोविड विपदा, हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मॉरीशस में गति के लिए मेट्रो एक्सप्रेस, न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट भवन, सुखद प्रवास के लिए सोशल हाउसिंग, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईएनटी अस्पताल, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई और रूपे कार्ड, सस्ती और बेहतर गुणवत्ता वाली दवाओं के लिए जन औषधि केंद्र, ऐसी अनेक जन केंद्रित पहल हैं, जिन्हें हमने समयबद्ध तरीके से पूरा किया है।

उन्होंने कहा, आज, प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम और मैंने भारत-मॉरीशस साझेदारी को बढ़ी हुई रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमने निर्णय लिया है कि भारत मॉरीशस में नए संसद भवन के निर्माण में सहयोग करेगा। यह लोकतंत्र की जननी की ओर से मॉरीशस को एक भेंट होगी।

इस दौरान मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी स्वतंत्रता की 57वीं वर्षगांठ के राष्ट्रीय दिवस समारोह में अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित किया है। उनकी विशिष्ट उपस्थिति हमारे दोनों देशों के बीच अद्वितीय और विशेष संबंधों का प्रमाण है।

भारत और मॉरीशस ने इन आठ समझौता ज्ञापनों पर किए हस्ताक्षर

- स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली पर मॉरीशस के केंद्रीय बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
- पाइप बदलने के कार्यक्रम के तहत केंद्रीय जल प्राधिकरण की ओर से चल रही परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए मॉरीशस सरकार और भारतीय स्टेट बैंक के बीच ऋण सुविधा पर समझौता
- राजनयिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम पर भारतीय विदेश सेवा संस्थान और मॉरीशस के विदेश, क्षेत्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन
- भारतीय नौसेना और मॉरीशस पुलिस बल के बीच श्वेत शिपिंग सूचना साझा करने पर तकनीकी समझौता
- मॉरीशस के वित्तीय अपराध आयोग और भारत के प्रवर्तन निदेशालय के बीच समझौता ज्ञापन
- मॉरीशस के उद्योग, एसएमई और सहकारिता मंत्रालय तथा भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के बीच सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन
- मॉरीशस के लोक सेवा और प्रशासनिक सुधार मंत्रालय तथा भारत के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के बीच लोक अधिकारियों के प्रशिक्षण पर समझौता ज्ञापन
- भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और मॉरीशस के प्रधान मंत्री कार्यालय के महाद्वीपीय शेल्फ, समुद्री क्षेत्र प्रशासन और अन्वेषण विभाग के बीच समझौता ज्ञापन

अहम बैठकों और संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, %मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस के विशेष अवसर पर मुझे अपने अच्छे मित्र प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम से मिलने और भारत-मॉरीशस मैत्री के सभी पहलुओं पर चर्चा करने का अवसर मिला। हमने अपनी साझेदारी को एक उन्नत रणनीतिक साझेदारी के रूप में बढ़ाने का निर्णय लिया है। हमने इस बारे में चर्चा की कि हम बुनियादी ढांचे, आवास, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में कैसे एक साथ काम कर सकते हैं। हम एआई, क्षमता निर्माण और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में और अधिक प्रगति करना चाहते हैं।

हरियाणा निकाय चुनाव में कांग्रेस की निकली हवा

चंडीगढ़। हरियाणा में महीनों पहले विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अपनी सत्ता कायम करते हुए, भाजपा के मेयर उम्मीदवार 10 नगर निगमों में से नौ में आगे चल रहे हैं, जिसमें रोहतक भी शामिल है - जो कांग्रेस के दिग्गज भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ है। पहली बार अपने चुनाव चिह्न पर राज्य निकाय चुनाव लड़ रही कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पा रहा है। भाजपा के मेयर उम्मीदवारों ने अंबाला, गुरुग्राम, सोनीपत, रोहतक और करनाल में जीत हासिल की है। यह फरीदाबाद, पानीपत, हिसार और यमुनानगर में आगे चल रही है। मानेसर में, निर्दलीय उम्मीदवार इंद्रजीत यादव ने भाजपा के सुंदर लाल को हराया। अंबाला में भाजपा की शैलजा सचदेवा ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस की अमीषा चावला को 20,487 मतों से हराकर महापौर पद पर जीत हासिल की। गुरुग्राम में भाजपा की राज रानी ने महापौर पद पर जीत हासिल की, जबकि सोनीपत में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव जैन ने कांग्रेस की कोमल दीवान को हराया। करनाल में भाजपा की रेणु बाला गुप्ता ने कांग्रेस के मनोज वाधवा को हराया।

हालांकि, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी रोहतक में हुई, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है। रोहतक में भाजपा के राम अवतार ने कांग्रेस के सूरजमल किलोई को हराया। 2024 के विधानसभा चुनावों में, कांग्रेस ने रोहतक और झज्जर जिलों पर अपनी पकड़ बनाए रखी, जिसमें पार्टी ने आठ में से सात सीटें जीतीं। हालांकि, हुड्डा ने कहा कि नगर निकाय चुनाव के नतीजों का कांग्रेस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। हुड्डा ने कहा कि पहले भी नगर निगमों में भाजपा का दबदबा रहा है। अगर हम सीट हार जाते तो यह झटका होता, लेकिन यह पहले से ही हमारे पास नहीं था।

मैं हिंदू हूं, और मुझे भाजपा से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं: ममता

सुवेंदु अधिकारी के बयान ममता की दो टूक

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र स्थायी है, लेकिन कुर्सी नहीं। कुर्सी का सम्मान करें। आप मुस्लिम विधायकों को बाहर निकालने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। वे (बीजेपी) मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं क्योंकि यह रोज़ा का महीना है, और उन्हें यह पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि वे सांप्रदायिक बयान देकर देश का ध्यान आर्थिक और व्यापार पतन से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक हिंदू हूं, और मुझे बीजेपी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में हिंदू मंदिरों पर हमलों के खिलाफ भाजपा ने विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के नेता सुवेन्दु अधिकारी ने कहा कि पिछले 4-5 दिनों से बरुईपुर, बशीरहाट में हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने दावा किया कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत का जश्न मना रहे लोगों पर हमला किया गया। इसके खिलाफ भाजपा विधायक ने विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाया, लेकिन उन्हें बोलने तक नहीं दिया गया।

विपक्ष के नेता ने दावा किया कि यह गैरकानूनी है और पश्चिम बंगाल की जनता की आवाज को दबाने की कोशिश है, जिसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि मांग यह है कि भेदभाव बंद किया जाना चाहिए। वोट बैंक और मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए, हिंदुओं को किनारे किया जा रहा है। हमारे मुख्य सचेतक डॉ. शंकर घोष ने हमारे मुद्दे उठाए और हमेशा की तरह उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी गई। हम इस निरंकुशता को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

खेल
प्रमुख समाचार

नॉकआउट मैच में मुंबई के सामने गुजरात की चुनौती

मुंबई। महिला प्रीमियर लीग का तीसरा संस्करण नॉकआउट स्टेज पर पहुंच चुका है। दिल्ली कैपिटल्स अंक तालिका में शीर्ष रहते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है जबकि सभी को दूसरी फाइनलिस्ट टीम का इंतजार है। मुंबई इंडियंस और गुजरात जाएंट्स के बीच एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाना है। यह मैच गुरुवार को मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले की विजेता टीम दिल्ली के खिलाफ 15 मार्च को फाइनल खेलेगी।

एलिमिनेटर में मुंबई इंडियंस घरेलू परिस्थितियों का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करेगी। मुंबई ने सोमवार को इसी मैदान पर लीग चरण के मैच में गुजरात को नौ रन से हराया था। इस मैच में हरमनप्रीत ने 33 गेंद पर 54 रन की तूफानी पारी खेली थी। मुंबई इंडियंस के अपनी टीम में किसी तरह का बदलाव करने की संभावना नहीं है।

हीली मैथ्यूज ने उन्हें अच्छी शुरुआत दी है और साथ ही अपनी ऑफ स्पिन से विरोधी टीम को परेशान भी किया है। वेस्टइंडीज की इस ऑलराउंडर ने गुजरात के खिलाफ लीग चरण के दोनों मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था और वह फिर से मैच विजेता बन सकती है। गुजरात के खिलाफ पिछले दोनों मैच में उन्होंने तीन-तीन विकेट लिए।

मुंबई इंडियंस के लिए बल्लेबाजी में नेट सिवर-ब्रंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने आठ मैच में 416 रन बनाए हैं और वह टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज है। गुजरात के गेंदबाजों को उन पर अंकुश लगाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। उन्होंने अपनी गेंदबाजी से भी अच्छा योगदान दिया है। मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत ने इस सत्र में अभी तक अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई है लेकिन गुजरात के खिलाफ सोमवार को खेले गए मैच में अर्धशतक बनाने से उनका मनोबल बढ़ा होगा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 73 अंक गिरकर बंद निफ्टी 22,470 पर आया

नईदिल्ली। ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले रुझानों के बीच आईटी शेयरों में बिकवाली के कारण बुधवार को बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी मामूली नुकसान के साथ बंद हुए। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 170 अंकों की बढ़त के साथ 74,270 पर खुला और जल्दी ही 74,392 के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया। सेंसेक्स दिन के उच्चतम स्तर से 794 अंक गिरकर 73,598 के निचले स्तर तक फिसल गया। अंत में, सेंसेक्स 73 अंक यानी 0.1% की मामूली गिरावट के साथ 74,030 पर बंद हुआ। बीएसई बेंचमार्क इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 39 अंक की चढ़कर 22,536 पर खुला। दिन के दौरान यह 22,577 के उच्चतम स्तर को छूने के बाद 22,330 के निचले स्तर तक गिरावट दर्ज की। अंत में, निफ्टी 27 अंकों की हल्की गिरावट के साथ 22,470 पर बंद हुआ।

गोल्ड ईटीएफ में निवेश लगातार 10वें महीने बढ़ा

नईदिल्ली। इक्विटी में लगातार गिरावट और ग्लोबल अनिश्चितता के बीच भारत में फरवरी के दौरान गोल्ड ईटीएफ में 1,979.84 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश हुआ। यह लगातार 10वां महीना है जब घरेलू स्तर पर गोल्ड ईटीएफ में नेट इनफ्लो दर्ज किया गया है। इससे पहले बीते साल अप्रैल में गोल्ड ईटीएफ में नेट आउटफ्लो देखा गया था। एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों के अनुसार देश के कुल 19 गोल्ड ईटीएफ में पिछले महीने 1,979.84 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश हुआ। पिछले साल की समान अवधि यानी फरवरी 2024 के मुकाबले यह 99 फीसदी ज्यादा है। पिछले साल इसी महीने के दौरान देश के कुल 17 गोल्ड ईटीएफ में 997.22 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश हुआ था। जनवरी 2025 के मुकाबले देखें तो इसमें 89 फीसदी की गिरावट आई है।

फरवरी में इक्विटी इनफ्लो 26 प्रतिशत घटा

नईदिल्ली। शेयर बाजार में जारी उतार-चढ़ाव का असर म्युचुअल फंड निवेश पर भी दिख है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया द्वारा बुधवार 12 मार्च को जारी आंकड़ों के अनुसार, फरवरी 2025 में इक्विटी म्युचुअल फंड में इनफ्लो 26% घटकर रू. 29,303.34 करोड़ रह गया। फरवरी के आंकड़े यह भी दिखाते हैं कि ओपन-एंडेड इक्विटी फंड्स में लगातार 48वें महीने भी नेट इनफ्लो पॉजिटिव बना रहा। हालांकि, यह गिरावट ऐसे समय में आई है जब बाजार में तेज करेक्शन (गिरावट) देखने को मिला। एसआईपी इनफ्लो में भी हल्की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इनफ्लो का स्तर मजबूत बना हुआ है। फरवरी 2025 में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) के जरिए म्युचुअल फंड में कुल रू. 25,999 करोड़ का इनफ्लो आया जो जनवरी 2025 के रू. 26,400 करोड़ के मुकाबले थोड़ा कम है।

अमेरिका में एल्युमिनियम और स्टील के आयात पर टैरिफ लागू

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने बुधवार (12 मार्च) को आधिकारिक तौर पर सभी स्टील और एल्युमिनियम आयात पर टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया। उन्होंने कहा कि इस टैरिफ वृद्धि से शेयर बाजार में बिकवाली के बावजूद नौकरियां पैदा होंगी। हालांकि, उनकी लगातार बदलती टैरिफ नीतियां शेयर बाजार में अस्थिरता पैदा कर रही हैं और आर्थिक मंदी की चिंताओं को बढ़ा रही हैं। ट्रंप ने 2018 में लगाए गए स्टील और एल्युमिनियम टैरिफ से सभी छूट हटा दी है और एल्युमिनियम पर टैरिफ 10% से बढ़ा दिया है। यह कदम फरवरी में जारी एक निर्देश के तहत उठाया गया है और इसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार को बाधित और पुनर्गठित करना है। इसके अलावा, अमेरिका ने कनाडा, मैक्सिको और चीन पर अलग-अलग टैरिफ लागू किए हैं।

भारत ने अमरीका से अधिक तेल खरीदने का वादा क्यों किया

एन. रवि कुमार

टैरिफ की धमकियों के बीच वाशिंगटन में फरवरी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात की, तब भारत ने अमरीका से अधिक तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने की प्रतिबद्धता जताई थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत की अमरीका से ऊर्जा खरीद पिछले साल के 15 बिलियन डालर से बढ़कर निकट भविष्य में 25 बिलियन डालर हो सकती है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है। एक ऐसे देश के लिए जो अपनी 85 प्रतिशत से अधिक कच्चे तेल की आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर करता है, हाइड्रोकार्बन आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए कोई भी कदम महत्वपूर्ण है।

भारत ने अमरीका से तेल और गैस की खरीद बढ़ाने का वादा किया है, जो ऊर्जा संबंधों को मजबूत करेगा और अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 500 बिलियन डालर तक पहुंचाने में भी कुछ हद तक मदद करेगा। वर्तमान में, द्विपक्षीय व्यापार भारत के पक्ष में है। अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के आंकड़े बताते हैं कि भारत के साथ माल व्यापार घाटा 2024 में 45.7 बिलियन डालर था, जो 2023 से 5.4 प्रतिशत वृद्धि है। भारत ने 2023-24 में कुल 234.26 मिलियन टन कच्चे तेल का आयात किया। पिछले वित्त वर्ष में 87.4 प्रतिशत के मुकाबले आयात निर्भरता 87.8 प्रतिशत हो गई। घरेलू उत्पादन आवश्यकता के 13 प्रतिशत से कम है, घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन पिछले वित्त वर्ष (2023-24) में 29.36 मिलियन टन पर लगभग अपरिवर्तित रहा। 2023-24 में आयात बिल कम अंतर्राष्ट्रीय दरों के कारण साल-दर-साल घटकर 133.37 बिलियन डालर हो गया।

2022-23 में तेल आयात बिल 157.53 बिलियन डालर था। इसके अतिरिक्त, भारत ने एल.पी.जी., ईंधन तेल और पेटकोक जैसे 48.69 मिलियन टन पैट्रोलियम उत्पादों के आयात पर 22.93 बिलियन डालर खर्च किए। भारत एल.एन.जी. का भी आयात करता है। 2023-24 में, देश ने 13.405 बिलियन डॉलर में 31.80 बिलियन क्यूबिक मीटर (बी.सी.एम.) का आयात किया। पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में कहा कि पिछले वित्त वर्ष में गैस का आयात 17.11 बिलियन डालर में 26.30 बी.सी.एम. था, जिसमें यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के मद्देनजर 2022-23 के मूल्य झटके का हवाला दिया गया था।

हाल के वर्षों में, अमरीका भारत को एल.एन.जी. के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में उभरा है। यदि रूस के खिलाफ युद्ध-संबंधी प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं, तो यूरोप फिर से रूस से प्राकृतिक गैस प्राप्त करना शुरू कर सकता है, जिससे अमरीका अन्य मौजूदा ग्राहकों को आपूर्ति बढ़ाने और नए बाजारों की तलाश करने के प्रयासों को तेज कर देगा। तेल की आपूर्ति में वृद्धि ने वैश्विक बाजारों में अनुकूल परिस्थितियां पैदा की हैं। पश्चिमी गोलार्ध से नए तेल स्रोतों का उदय, जिसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, सूरीनाम, कनाडा, अमरीका और गुआना शामिल हैं, भारत जैसे प्रमुख उपभोक्ता देशों के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है।

भारत, जो परंपरागत रूप से पश्चिम एशिया से तेल प्राप्त करता रहा है, ने यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस से बड़ी मात्रा में तेल आयात करना शुरू कर दिया। इसके कारण भारत के रूसी तेल आयात में नाटकीय वृद्धि देखी गई, जो कि थोड़े समय में ही उसके कुल कच्चे तेल आयात के 1 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया। आई.ई.ए. ने अपनी इंडिया गैस मार्केट रिपोर्ट 'आउटलुक टू 2030' में कहा है कि देश की गैस खपत दशक के अंत तक सालाना 103 बी.सी.एम. तक पहुंच जाएगी। धीमी वृद्धि और समय-समय पर गिरावट के एक दशक से उभरकर, देश की प्राकृतिक गैस की मांग 2023 और 2024 दोनों में 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई है, जो एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत है।

होली मिलन समारोह में विधानसभा परिसर हुआ रंग-गुलाल से सराबोर

रायपुर। विधानसभा परिसर में आज होली मिलन समारोह का रंगारंग आयोजन हुआ, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत सहित तमाम विधायकों ने एक-दूसरे को रंग-गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएँ दीं। आयोजन का पूरा माहौल होली के उल्लास में सराबोर रहा। मंत्रियों और विधायकों ने पारंपरिक फाग गीतों की मनमोहक प्रस्तुति दी, जिस पर विधानसभा सदस्य झूमते नजर आए।

होली मिलन समारोह में लोक परंपरा का विशेष रंग देखने को मिला। मंत्री-विधायकों द्वारा गाए गए फाग गीतों से विधानसभा परिसर में सांस्कृतिक समृद्धि की झलक दिखी।

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया गीत की मधुर प्रस्तुति दी।विधायक अनुज शर्मा ने का तैं मोला मोहिनी डाल दिये रे और रंग बरसे गीत गाकर समां बांध दिया। विधायक कुंवर सिंह निषाद ने फागुन मस्त महीना और चना के डार राजा गीत गुनगुनाया। विधायक दिलीप लहरिया ने नदिया के पार म, कदली कछार म गीत सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।

लोकप्रिय कवि डॉ. सुरेंद्र दुबे ने अपनी हास्य और होली की रंगीन कविताओं से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके अलावा राकेश तिवारी और उनकी टीम ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समां बांध दिया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ. सुरेंद्र दुबे, राकेश तिवारी व उनकी टीम को सम्मानित किया।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव, वनमंत्री केदार कश्यप, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, विधायक अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक, पुरंदर मिश्रा, धर्मजीत सिंह, मोतीलाल साहू, सुशांत शुक्ला, संदीप साहू, गुरु खुशवंत साहेब, भैयालाल राजवाड़े, ईश्वर साहू, कुंवर सिंह निषाद, रिकेश सेन, रामकुमार यादव, श्रीमती भावना बोहरा, योगेश्वर राजू सिन्हा, अटल श्रीवास्तव, ललित चंद्राकर सहित विधानसभा के अधिकारी, कर्मचारी एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

रायपुर प्रेस क्लब के होली मिलन समारोह में सीएम साय हुए शामिल

रायपुर। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करने का अवसर भी है। यह पर्व हमें छोटी-छोटी अनबन को भुलाकर नए सिरे से दोस्ती की शुरुआत करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री साय का रायपुर प्रेस क्लब के सदस्यों ने अनूठे अंदाज में भिंडी की माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रेस क्लब के होली विशेषांक 'सेंसलेस टाइम्स' का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रायपुर प्रेस क्लब में पर्वों को मिल-जुलकर मनाने की एक गौरवशाली परंपरा है। हर साल इस होली उत्सव में शामिल होने का अवसर मिलता है। मैं रायपुर प्रेस क्लब परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हर्ष और उल्लास से भरा यह पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करे, यही मेरी मंगलकामना है। रायपुर प्रेस क्लब के होली मिलन समारोह में रंगों और उमंग का अनोखा नज़ारा देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने खुद नगाड़ा बजाकर उत्सव का जोश दोगुना कर दिया। मुख्यमंत्री के नगाड़ा बजाते ही समारोह में मौजूद पत्रकारों और गणमान्यजनों ने तालियों से उत्साह बढ़ाया और पूरे माहौल में उल्लास की लहर दौड़ गई। पारंपरिक ढोल-नगाड़ों की धुन पर मुख्यमंत्री भी पत्रकारों के साथ फाग गीतों और होली की मस्ती में झूमते नजर आए।

मुख्यमंत्री ने किया 'गुलाल' होली विशेषांक का विमोचन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में श्रमजीवी गिल्ड फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित होली विशेषांक 'गुलाल' का विमोचन किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री साय ने 'गुलाल' विशेषांक की सराहना करते हुए इसके प्रकाशन के लिए फाउंडेशन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि होली उल्लास, प्रेम और सौहार्द का पर्व है, और यह विशेषांक भी इन्हीं मूल्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। जैसे होली के रंग आपसी भाईचारे और सकारात्मकता का प्रतीक होते हैं, वैसे ही यह पत्रिका समाज में खुशियों का संचार करेगी।

फाउंडेशन के सदस्यों ने मुख्यमंत्री साय को अवगत कराया कि अब तक 'गुलाल' विशेषांक का प्रकाशन कोरिया और सरगुजा से होता रहा है, लेकिन इस बार इसे राजधानी रायपुर से प्रकाशित किया गया है। इस अवसर पर आर.के. गांधी, दीपक विश्वकर्मा, जगजीत सिंह, श्रीकांत यदु एवं सुजिज्ञासा चंद्रा सहित अन्य गणमान्य पत्रकार उपस्थित थे।

कांग्रेस ने तो सीबीआई को बैन किया था, अब कैसे भरोसा हो गया? : सीएम साय

रायपुर । विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भारतमाला परियोजना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की। जिस पर जवाब देते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि, यह वही कांग्रेस है, जिसने अपने कार्यकाल के दौरान सीबीआई को बैन कर दिया था। लेकिन अचानक इन्हें सीबीआई पर भरोसा हो गया है और ये सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस अपने स्वार्थ अनुसार कथन बदलती है और इनकी कथनी और करनी में अंतर है।

उल्लेखनीय है कि, विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत ने भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी की जांच छ्वक्चढ्ढ से कराने की मांगी की है।सदन में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास ने 32 प्लॉटों को 247 टुकड़ों में बांटे जाने को लेकर प्रश्न पूछा। जिसके जवाब में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि, कलेक्टर रायपुर के जांच प्रतिवेदन में जानकारी आई है। नायकबांधा में 13 खसरों को 53 प्लॉटों में बांटा गया है, फर्जी नामांतरण से शासन को क्षति होना पाया गया है। मामले में नायब तहसीलदार, 3 पटवारी निलंबित किए गए हैं। तत्कालीन तहसीलदार अभनपुर के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।

जांच में कहीं हीलाहवाला नहीं किया जाएगा- मुख्यमंत्री साय: मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बड़ा बयान देते हुए कहा- जांच में कहीं हीलाहवाला नहीं किया जाएगा। कांग्रेस सरकार ने तो छत्तीसगढ़ में सीबीआई को बैन किया था। नेता प्रतिपक्ष ने विधायकों की समिति बनाकर जांच की मांग की। मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा- कमिश्नर से मामले की जांच कराई जाएगी। कमिश्नर की जांच से असंतुष्ट विपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर तीखी बहस की। मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा- अफसर निलंबित हुए हैं। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

भावना बोहरा ने सदन में उठाए पत्रकार सुरक्षा, शिक्षा और मछली पालन पर सवाल

रायपुर। पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने विधानसभा में प्रदेश के पत्रकारों की सुरक्षा, शिक्षा व्यवस्था और मछली पालन योजनाओं को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने बस्तर संभाग के बीजापुर में दिवंगत पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का मुद्दा उठाते हुए सरकार से पत्रकारों की सुरक्षा नीति पर जवाब मांगा। इसके साथ ही, उन्होंने नए स्कूलों की स्थापना और शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इसके अलावा, उन्होंने मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी भी मांगी।

पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सवाल: विधायक बोहरा ने पूछा कि बस्तर संभाग (बीजापुर) के दिवंगत पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सरकार की क्या नीति है? क्या दुर्घटनाओं में पंजीकृत पत्रकारों को मुआवजा या चिकित्सा सहायता का प्रावधान है? इस पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लिखित उत्तर में बताया कि छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा अधिनियम-2023 प्रक्रियाधीन है। जनसंपर्क विभाग में पत्रकारों का पंजीकरण नहीं किया जाता। हालांकि, छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियम-2019 के तहत पत्रकारों और उनके परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 10,000 से 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। पत्रकार की असामयिक मृत्यु होने पर परिवार को 5 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है।

शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा: भावना बोहरा ने पूछा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश में कितने नए स्कूल स्वीकृत हुए हैं और प्रदेश में स्कूल ड्रॉपआउट दर कितनी है? मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस वित्तीय वर्ष में 16 नए प्राथमिक स्कूल स्वीकृत हुए हैं। नीति आयोग के अनुसार, छत्तीसगढ़ की शिक्षा रैंकिंग आकांक्षी एक श्रेणी में 521-580 के बीच है। यूडाईस डेटा 2023-24 के मुताबिक, प्राथमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर 1.8%, उच्च प्राथमिक स्तर पर 5.3% और हाईस्कूल स्तर पर 16.3 % है।

मछली पालन को बढ़ावा देने की योजनाएं: मछली पालन योजनाओं के तहत मिलने वाली सहायता पर सवाल उठाते हुए विधायक बोहरा ने पूछा कि कबीरधाम जिले में अनुसूचित जाति और जनजाति के कितने किसानों को अनुदान मिला है। मुख्यमंत्री ने उत्तर दिया कि सरकार 10 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए 1250 रुपये प्रति हितग्राही, 3 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए 1000 रुपये प्रति हितग्राही और अध्ययन भ्रमण के लिए 2500 रुपये प्रति हितग्राही अनुदान देती है।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

मृत्यु के कारणों के चिकित्सकीय प्रमाणीकरण पर कार्यशाला आयोजित

रायपुर। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा राज्य में मृत्यु के कारणों के चिकित्सकीय प्रमाणीकरण (एमसीसीडी) विषय पर राजधानी रायपुर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में राज्यभर के चिकित्सकों, जनगणना निदेशालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अपर संचालक ने एमसीसीडी की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए अस्पतालों से अधिक संख्या में एमसीसीडी प्रपत्र प्राप्त करने और आंकड़ों की गुणवत्ता सुधारने करने, एमसीसीडी की प्रक्रिया को बेहतर बनाने और विभिन्न विभागों में समन्वय पर जोर दिया। जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़ के उप निदेशक ने एमसीसीडी में अब तक किए गए प्रयासों की जानकारी दी और राज्यभर के अस्पतालों से एमसीसीडी प्रपत्रों के संग्रहण की आवश्यकता पर जोर दिया।

होली पर अम्बेडकर अस्पताल में 24 घंटे जारी रहेगी चिकित्सा सेवा

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल और स्वास्थ्य मंत्री श्री श्यामबिहारी जायसवाल के दिशानिर्देश पर होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए अम्बेडकर अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने की व्यवस्था की गई है। अस्पताल अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर ने डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रहने के लिए निर्देशित किया है। होली के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना या आपातकालीन चिकित्सा स्थिति के संभावित मामलों को देखते हुए आपात चिकित्सा सेवाओं को चौबीसों घंटे चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं। होली के दिन 14 मार्च को शासकीय अवकाश होने के कारण ओपीडी (बाह्य रोगी विभाग) बंद रहेगा, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं पूर्ववत 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी।आपातकालीन वार्डों में जीवन रक्षक दवाओं और आवश्यक संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। मेडिकल स्टाफ को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल सहायता दी जा सके। सभी डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को इमरजेंसी ड्यूटी के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। मरीजों को समय पर इलाज मिल सके।

सतत विकास लक्ष्य पर नीति आयोग की संभागीय कार्यशाला

बिलासपुर। सतत विकास लक्ष्य पर संभाग स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आज प्रार्थना सभाभवन के सभाकक्ष में किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए संभागायुक्त श्री महादेव कावरे ने कहा कि सतत विकास का उददेश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए सामाजिक और आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करना है। राज्य नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य के जिलों में बेहतर क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग में सुविधा हेतु एसडीजी डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क में सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय एवं अन्य पहलुओं संबंधी कुल 82 इंडिकेटर का समावेश किया गया है। कार्यशाला में राज्य नीति आयोग के सदस्य डॉ. के सुब्रमण्यम, नीति आयोग के सदस्य सचिव डॉ.नीतू गोर्डिया, जिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी श्री संदीप अग्रवाल सहित संभाग के सभी जिलों के अधिकारी मौजूद थे। श्री कावरे ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 में 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए थे, जिन्हें 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला का मुख्य उददेश्य विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए, इस पर विचार विमर्श करना था। रैकिंग के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ को 69 अंक हासिल हुए हैं।

कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर की दौड़ में शामिल

रायपुर। अपनी समृद्ध जैव विविधता और जीव जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियों के आवास के रूप में पहचाने जाने वाले बस्तर के कांगेर घाटी नेशनल पार्क को यूनेस्को ने 2025 की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तदर्थ सूची में शामिल कर लिया है। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा हासिल करने के लिए राज्य सरकार को एक साल में अपना दावा पूरे तथ्यों के साथ पेश करना होगा। कांगेर घाटी को टेंटेटिव लिस्ट में भी शामिल किया जाना भी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहली बार किसी साइट को यह मौका मिला है। 200 वर्ग किमी में फैला कांगेर घाटी नेशनल पार्क कई वजहों से खास है। करीब दो साल पहले कांगेर घाटी नेशनल पार्क के तत्कालीन डायरेक्टर गणवीर धम्मशील ने करीब साल भर की तैयारी और रिसर्च, पुरातत्व विभाग समेत कई विभागों की शोध के आधार पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नेशनल पार्क का प्रस्ताव यूनेस्को को भेजा था।

सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक अटेण्डेन्स अनिवार्य

बिलासपुर। विलम्ब से दफ्तर आने वाले सरकारी कर्मचारियों की अब खैर नहीं होगी। बायोमेट्रिक अटेन्डेन्स के आधार पर उनका अगले महीने से वेतन निकाला जायेगा। कलेक्टर अवनीश शरण ने अधिकारी-कर्मचारियों की लेटलतीफी से आम जनता को हो रही परेशानी को गंभीरता से लिया है। उन्होंने जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक मशीन लगाने के निर्देश दिए हैं। मशीन लगाने के लिए 15 दिवस की मोहलत प्रदान की है। अप्रैल महीने का वेतन हर हाल में बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही ड्रा किया जायेगा। कलेक्टर ने जिले के सभी विभाग प्रमुख, अतिरिक्त कलेक्टर, जिला कार्यालय एवं सभी प्रभारी अधिकारियों को आज इस आशय कड़े पत्र जारी किये हैं। जिसके अनुसार प्राय: यह देखा जा रहा है कि शासन द्वारा निर्धारित कार्यालयीन समय पर अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आपका स्वयं एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति कोई नियंत्रण नहीं है। इससे जहां एक ओर शासकीय कार्य का त्वरित निपटारा नहीं हो पाता है वहीं आम जनता को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति अत्यंत खेदजनक एवं चिंताजनक है। कलेक्टर ने कहा है कि बायोमेट्रिक व्यवस्था का वे स्वयं आकस्मिक निरीक्षण करेंगे।

अग्निशमन सेवाओं के विस्तार पर सांसद बृजमोहन ने लोकसभा में उठाया सवाल

देश में अग्निशमन केंद्रों की 97.54त्न कमी सांसद बृजमोहन के सवाल पर गृहमंत्रालय का जवाब

छत्तीसगढ़ में 12 नए अग्निशमन केंद्रों की होगी स्थापना- सांसद बृजमोहन

नई दिल्ली/रायपुर। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में छत्तीसगढ़ में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण को लेकर गृह मंत्रालय से सवाल किया। उन्होंने जानना चाहा कि पिछले तीन वर्षों में इस योजना के तहत राज्य में क्या पहल की गई, कितनी राशि आवंटित और उपयोग की गई, तथा अग्निशमन अवसंरचना की कमियों और उनके समाधान के लिए सरकार की क्या योजना है।

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जवाब देते हुए बताया कि पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 5000 करोड़ रुपये की योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य को 147.745 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 33.24 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की जा चुकी है।

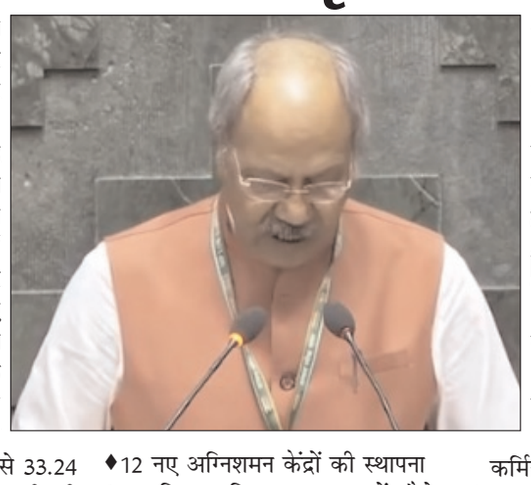

छत्तीसगढ़ में निर्धारित लक्ष्य

- 12 नए अग्निशमन केंद्रों की स्थापना
- आधुनिक अग्निशमन उपकरणों जैसे फायर टेंडर, हाई एक्सपेंशन फोम जनरेटर, सेमी-ऑटोमेटिक डिफाइब्रिलेटर, स्मोक एक्सट्रैक्टर आदि की खरीद
- अग्निशमन कर्मियों का क्षमता निर्माण प्रशिक्षण
- राज्य के अग्निशमन सेवा मुख्यालय को मजबूत करने का कार्य किया जाएगा।

देश में अग्निशमन की स्थिति

- देश में अग्निशमन केंद्रों की 97.54 फीसदी कमी है।
- 80.04 फीसदी अग्निशमन एवं बचाव वाहन की कमी है।
- 96.28 फीसदी अग्निशमन कर्मियों की आवश्यकता बनी हुई है।

योजना की निगरानी और क्रियान्वयन

गृह मंत्रालय के अनुसार, अग्निशमन सेवाएं राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, लेकिन केंद्र सरकार सलाहकार भूमिका निभा रही है। राज्यों को अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 2026 तक लक्ष्य पूरे करने होंगे। इसके लिए महानिदेशक (एफएस, सीडी और एचजी) के साथ समझौता ज्ञापन (रूष्ठ) पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राज्य में अग्निशमन सेवाओं को आधुनिक और प्रभावी बनाना बेहद जरूरी है, ताकि आपातकालीन स्थितियों में बेहतर प्रतिक्रिया दी जा सके। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि छत्तीसगढ़ में इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और राज्य को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।

जन शिक्षण संस्थान रायपुर ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया

रायपुर। दिनांक 11 मार्च 2025 को जन शिक्षण संस्थान रायपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) को ध्यान में रखते हुए शासकीय महिला पॉलिटेक्निक के सभागार में अपने संस्थान की उत्कृष्ट प्रशिक्षिकाओं के साथ साथ इस वर्ष के 90 बैचेस में से लगभग 35 बैच के 700 प्रशिक्षार्थियों जिनका मूल्यांकन 31 दिसंबर के पूर्व कर लिया गया हैं उन सभी को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह रायपुर एवं बिलासपुर संभाग के संभागायुक्त एवं कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति महादेव कावरे (ढ्ढस्र) के मुख्य आतिथ्य एवं जन शिक्षण संस्थान रायपुर के अध्यक्ष (सेवानिवृत ढ्ढस्र) की अध्यक्षता में एवं संस्थान के सभी बोर्ड के सदस्यता एवं स्टॉफ मेंबर तथा सभी रिसोर्स पर्सन्स की उपस्थिति में संपन्न किया गया।मुख्य अतिथि महादेव कावरे जी ने कहा कि यह दिन समाज में महिलाओं की भूमिका, संघर्ष और सफलता को दर्शाता है। महिला दिवस का दिन महिलाओं की समानता, अधिकारों और उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। महिलाओं में कौशल जन्मजात होती हैं साथ ही कौशल के माध्यम से कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना और उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.